https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

रामनाथ कोविंद बने राजग के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

वर्ष-12, अंक-13, 01-15 जुलाई, 2017 (पाक्षिक) ₹20

योग ने दुनिया को भारत से जोड़ा

शिमला नगर निगम चुनाव: भाजपा ने रचा इतिहास

लैटिन अमेरिका पहुंचा योग का जादू

कृषि क्षेत्र का चहुंमुखी विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने जाते श्री रामनाथ कोविंद

खेड़ा नडियाद (गुजरात) में जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

रायपुर (छत्तीसगढ़) में केंद्र–राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिला का अभिनंदन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

आज योग घर-घर का हिस्सा: नरेंद्र मोदी

06

तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को देश-विदेश में लाखों लोगों ने योग-आसन और प्राणायाम कर निरोग रहने का संदेश दिया। पेरु से लेकर चीन तक और लखनऊ के रमाबाई मैदान से दिल्ली के कनॉट प्लेस तक भारत में और विश्व के...

वैचारिकी

लोकसभा में विरोधी पक्ष के प्रमुख नेता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी 15

श्रद्धांजलि

स्वामी विवेकानंद 18

लेख

अद्भुत 3 साल, 3 गुना महिला विकास 20

लैटिन अमेरिका पहुंचा योग का जादू 22

आपातकाल का एक शर्मनाक अध्याय 24

अन्य

रामनाथ कोविंद बने राजग के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 09

'मोदी सरकार ने गरीबों को देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ा' 12

'बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान' 15

प्रधानमंत्री ने स्वामी आत्मस्थानंदजी के निधन पर शोक व्यक्त किया 17

शिमला नगर निगम चुनाव: भाजपा ने रचा इतिहास 19

कृषि क्षेत्र का चहुंमुखी विकास 26

पीएसएलवी-सी38 ने सफलतापूर्वक एक साथ प्रक्षेपित किए... 28

जीएसटी कार्यान्वयन के पहले दो माह में कर विवरण दाखिल... 29

रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी में शुरु राजनीति की पाठशाला 30

विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान... 31

संगठनात्मक गतिविधियां

10 अपनी संस्कृति बनाए रखते हुए हम नवीन कार्यपद्धति का निर्माण करें : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष...

11 'हमारे पांच साल का काम उनके 50 साल के काम पर भारी पड़ेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज गुजरात के दो...

सरकार की उपलब्धियां

13 मंत्रिमंडल ने दी फसल ऋण पर ब्याज अनुदान को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को वर्ष...

14 मसाला निर्यात में अब तक की सबसे अधिक रिकॉर्ड 12 प्रतिशत की वृद्धि

दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई कड़े नियमों के लागू होने के बावजूद भारत के मसाला...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी करवा सकता है।

@rajnathsingh

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंसा के जरिए किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। प्रत्येक समस्या को आपसी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है।

@arunjaitley

आपातकाल विरोधाभास से ग्रस्त चमचागिरी का काल है। प्रायः एक तानाशाही शासन अपने ही प्रोपगेंडे के द्वारा भटक जाता है।

@rsprasad

जीएसटी महज कर नहीं है, बल्कि यह भारत को एक बाजार विकसित करने की पहल है।

facebook

आज से 42 वर्ष पूर्व, राजनीतिक स्वार्थ के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर देशवासियों से सारे अधिकार छीन देश मे आपातकाल लगाया गया। देश के लाखों लोगों ने अनेकों यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए आंदोलन किये। भारतीय लोकतंत्र के उन सभी प्रहरियों को मेरा कोटि-कोटि नमन।

— अमित शाह

देश की आज़ादी के बाद जीएसटी भी टैक्स के मामले में बड़ी आज़ादी है। टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। छोटे व्यापारियों को जीएसटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारियों को राहत मिलेगी। अभी कई तरह की भ्रांतियां हैं। जैसे-जैसे स्थिति साफ होगी, व्यापारी इसका स्वागत करेंगे। व्यापारियों को इन्स्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी। जीएसटी से महंगाई कम होगी। आम आदमी को राहत मिलेगी। विलासिता की वस्तुएं थोड़ी महंगी होंगी। किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आम नागरिक के नाते किसान जीएसटी के लागू होने पर लाभान्वित होंगे। यह एक नई व्यवस्था प्रारम्भ हो रही है। थोड़ी समस्याएं सामने आयेंगी। जो भी दिक्कतें आयेंगी, उसके समाधान के लिए जीएसटी काउंसिल है। इसके लागू होने से आर्थिक विकास दर बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

—शिवराज सिंह चौहान

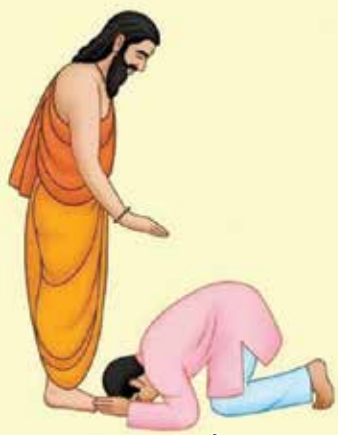

'कमल संदेश' की ओर से सुधी पाठकों को गुरु पूर्णिमा (9 जुलाई, 2017) की हार्दिक शुभकामनाएं!

पाथेय

भारत का इतिहास बहुत पुराना है। जब दुनिया अविकसित थी, तब भारत के मनीषी और ऋषियों ने मनुष्य जीवन सुखी कैसे हो? सार्थक कैसे हो? इस पर विचार किया। उस दिशा की ओर समाज कैसे आगे बढ़े? ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित कीं और लगातार जागरूक रहकर निर्लिप्ता से मनुष्य को उन प्रवृत्तियों का अभ्यास कराया। उसी में से हमारी सामाजिक धारणा बनी।

-कुशाभाऊ ठाकरे

कांग्रेस ने खोया अवसर

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिये बिहार के राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद का नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित किया, हर ओर इस निर्णय का स्वागत होने लगा। संपूर्ण एनडीए के साथ–साथ, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, जदयू, बीजद तथा अन्नाद्रमुक ने अब तक इस घोषणा का समर्थन किया है। जिस प्रकार का समर्थन श्री रामनाथ कोविंद को मिल रहा है, कुछ दिन पहले तक उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अधिकतर विश्लेषक अब तक राष्ट्रपति चुनाव में कड़े मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे। इस प्रकार का समर्थन आम सहमति बनाने के व्यापक बातचीत का परिणाम है, जिसमें लगभग हर राजनैतिक दल से भाजपा नेतृत्व ने संपर्क किया। वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में राजग ने लगभग आम सहमति बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। राष्ट्रपति पद की गरिमा एवं इससे जुड़े प्रतिष्ठा के अनुरूप इस बात का संतोष किया जा सकता है कि अनेक राजनैतिक दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के इस सबसे बड़े पद के लिये सर्वाधिक उपयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में देर नहीं की।

जहां एक ओर इस पद के लिये आम सहमति बनने की प्रक्रिया अपेक्षित परिणाम दे रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने श्री रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के स्थान पर राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जो कांग्रेस अभी तक दूसरे नामों को मीडिया में उछालती रही, उसे अब रामनाथ कोविंद के सामने एक दलित प्रत्याशी की घोषणा करने को बाध्य होना पड़ा। इसके पहले कांग्रेस ने दलित प्रत्याशी के विषय में कभी सोचा तक नहीं था, पर जब एक दलित प्रत्याशी की घोषणा हुई तब उनके सामने एक दलित प्रत्याशी को खड़ा करने की योजना बनाई गई। लेकिन तब तक कांग्रेस के लिये बहुत देर हो चुकी थी। कांग्रेस जो कम्युनिस्ट एवं अपने अन्य सहयोगियों के साथ बहुत पहले ही एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ सभी दलों को गोलबंद करने में लगी थी, सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि उसने इस पद को राजनैतिक चश्में से देखते हुए चुनाव के राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। यही कारण था कि वे एनडीए से बाहर के भी राजनैतिक दलों का समर्थन नहीं जुटा पाये। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस तथा इसके सहयोगियों के बीच का अंतर्विरोध भी कई बार उजागर हुआ। वास्तव में कांग्रेस को अपनी इच्छा के विरूद्ध मायावती जैसों के दबाव में ऐसे प्रत्याशी को आगे करना पड़ा, जिसके बारे पहले कभी इसने सोचा तक नहीं था। अब कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ केवल नाम के लिये एक ऐसे चुनावी मैदान में है, जिसमें वह पहले ही हार चुकी है। श्री रामनाथ कोविंद का समर्थन कर कांग्रेस देश में एक अच्छा संदेश भेज सकती थी, परन्तु अब ऐसा लगता है कि उसने इस अवसर को खो दिया है।

राष्ट्रपति पद के लिये व्यापक सहमति बनाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों ने व्यापक सहमति बनाने की प्रक्रिया का संचालन किया, उससे देश का लोकतंत्र अपने वास्तविक अर्थों में सुदृढ़ हुआ है। यह केवल कांग्रेस एवं कम्युनिस्टों की जिद थी जिस कारण इस गरिमापूर्ण पद के लिये आज चुनाव हो रहे हैं।

राष्ट्रपति पद के लिये व्यापक सहमति बनाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों ने व्यापक सहमति बनाने की प्रक्रिया का संचालन किया, उससे देश का लोकतंत्र अपने वास्तविक अर्थों में सुदृढ़ हुआ है। यह केवल कांग्रेस एवं कम्युनिस्टों की जिद थी जिस कारण इस गरिमापूर्ण पद के लिये आज चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि विपक्ष के रूप में उसे एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करना है। बार–बार बाधा उत्पन्न कर न तो वह कुछ अपना भला कर रही है न ही यह देश के व्यापक लोकतांत्रिक हित में है। राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए और जब भी अवसर मिले व्यापक सहमति बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर मजबूत करना चाहिये, लेकिन कांग्रेस से रचनात्मक भूमिका की अपेक्षा करना भी अपने आप में एक भूल होगी। क्योंकि अंधविरोध इसमें इतनी जड़ें जमा चुकी हैं कि यह 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' तक का विरोध करने से नहीं चूकती। योग जिसे आज पूरा विश्व भारत के एक उपहार के रूप में स्वीकार कर रहा है, जब कांग्रेस उसका भी राजनीतिकरण कर सकती है तब भला वह राष्ट्रपति चुनाव को कैसे छोड़ सकती है। फिर भी जिस प्रकार की व्यापक सहमति बनाने की प्रक्रिया चली तथा अनेक राजनैतिक दलों ने दलगल राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन दिया, उससे राष्ट्रपति पद के लिये बहुत ही व्यापक समर्थन संभव हुआ है तथा कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दल अलग–थलग पड़कर केवल प्रतीकात्मक चुनाव लड़ रहे हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

आज योग घर-घर का हिस्साः नरेंद्र मोदी

योग में 'शून्य लागत पर स्वास्थ्य बीमा' की ताकत

तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को देश-विदेश में लाखों लोगों ने योग-आसन और प्राणायाम कर निरोग रहने का संदेश दिया। पेरु से लेकर चीन तक और लखनऊ के रमाबाई मैदान से दिल्ली के कनॉट प्लेस तक भारत में और विश्व के देशों में 'ओऽम' का नाद गूंजा, जहां लोगों ने अध्यात्म तथा शारीरिक व्यायाम को जोड़ने वाली इस विधा का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, देहरादून, चंडीगढ़ में भी योग शिविर आयोजित किए गए। राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी योग किया। दफ्तरों, पार्कों और सड़कों तक पर लोग योग करने जमा हुए, जिनमें आम लोगों से लेकर राजनेता, नौकरशाह, न्यायाधीश भी शामिल थे।

योग दिवस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि योग की एक विशेषता मन को स्थिर रखने की है। किसी भी प्रकार के उतार-चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। योग स्वयं भी व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा है। एक समय में यह ऋषियों की साधना का ही मार्ग हुआ करता था, परन्तु आज योग घर-घर का हिस्सा बन रहा है। दुनिया के अनेक देश जो हमारी भाषा, संस्कृति नहीं जानते हैं, फिर भी योग के माध्यम से वे हमसे जुड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कम से कम समय में सर्वाधिक वोटों से योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति दी, जिसके चलते हर देश में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में योग के प्रति पूरे विश्व में आकर्षण बढ़ा है, नए-नए योग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, योग ट्रेनर्स की मांग बढ़ी है। लोग योग को प्रोफेशन के रूप में अपना रहे हैं। योग ने विश्व में एक नया जॉब मार्केट क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन व बुद्धि को जोड़ता है। पहले लोग योग को अपनी

योग की एक विशेषता मन को स्थिर रखने की है। किसी भी प्रकार के उतार-चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। योग स्वयं भी व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा है। एक समय में यह ऋषियों की साधना का ही मार्ग हुआ करता था, परन्तु आज योग घर-घर का हिस्सा बन रहा है।

तरह से करते थे, फिर इसका स्टैण्डर्डाइजेशन शुरू हुआ। पिछले वर्ष यूनेस्को ने योग को मानव संस्कृति की एक अमर विरासत के रूप में मान्यता दी है। विश्व के संगठन, स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को योग की ट्रेनिंग मिले और यह धीरे-धीरे उनके जीवन का हिस्सा बने, इसकी आवश्यकता बढ़ी है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत के कई राज्यों ने योग को शिक्षा का अंग बनाया है, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां इससे परिचित हो और इसकी अभ्यासी बनें। उन्होंने कहा कि हेल्थ के लिए कई प्रकार के प्रकल्प होते हैं, लेकिन फिटनेस और हेल्दी होने से भी ज्यादा वेलनेस का महत्व होता है। वेलनेस को सहजता से प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज योग के सामने दुनिया में कहीं पर भी सवालिया निशान नहीं है। इसमें समयानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं। विश्व के विभिन्न समाज इसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। स्थल, काल, परिस्थिति तथा आयु के अनुकूल योग में उत्तरोत्तर विकास और विस्तार होता रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह करते हुए इसका सफल अभ्यासी बनने की सलाह दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम पहली बार योग करते है तो शरीर के अनेक अंग जो सुसुप्तावस्था में रहते हैं, वे सक्रिय हो जाते है। योग से उनमें जागरूकता आने लगती है, वे चैतन्य हो जाते है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यदि जीवन में नमक न हो तो जीवन नहीं चलता। योग का हमारे जीवन में यही स्थान है। जीरो कॉस्ट से हेल्थ एश्योरेंस की ताकत योग में है। उन्होंने कहा कि यदि योग के माध्यम से देश के साथ-साथ पूरे विश्व के लोग स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ बुद्धि प्राप्त कर ले, तो मानव जाति के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से उसकी रक्षा हो सकती है।

योग कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग भारत की प्राचीन विधा है और हमारी ऋषि परम्परा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रन्थों ने योग के महत्व को स्वीकारा है। योग जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है।

गौरतलब है कि वर्षा होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय के बीच स्वयं पहुंचकर योग दिवस पर सभी योगाभ्यासियों के साथ योग किया। उन्होंने कई लोगों से हाथ भी मिलाया। उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से प्रधानमंत्री जी का सम्पूर्ण कार्यक्रम में अभिवादन भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्रियों श्री केशव प्रसाद मौर्य तथा डॉ0 दिनेश शर्मा ने भी योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपाद येस्सो नाईक सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा योग साधक मौजूद थे।

देश भर में योग शिविर

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में योग के शिविर लगाए

गए, जिसमें आम लोगों के साथ नेताओं और मशहूर हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। अहमदाबाद में आयोजित योग कार्यक्रम ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस योग शिविर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, बाबा रामदेव, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपानी भी मौजूदगी में एक साथ 1.50 लाख लोगों ने योग किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग के महत्व को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में योग का महत्व बढ़ रहा है।

इस योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हजारों लोगों ने योग आसन किया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क और आस-पास की सड़कों पर दस हजार से अधिक लोग एकत्रित हुए। यह शहर का सबसे बड़ा योग कार्यक्रम रहा। इसमें स्कूली विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेता, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने योग मुद्रा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने योग को अंतर्राष्ट्रीय कला बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में की गई पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारी प्राचीन परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली। योग न तो राजनीतिक है और न ही धार्मिक, बल्कि सदियों से व्यवहार में लाए जाने वाला पारंपरिक भारतीय कला अभ्यास है। इससे शांति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और एकात्मकता आती है। योग एक विज्ञान है इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य पूर्ण विकास है।

श्री नायडू ने निर्माण भवन में योग कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए इस अभियान में सभी से शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि योग समाज के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में योग दिवस मनाने और योग आसन करने से लोगों को योग के लाभ के बारे में जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि योग सार्वभौमिक परंपरागत अभ्यास है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया। यह लोगों में एकता लाता है।

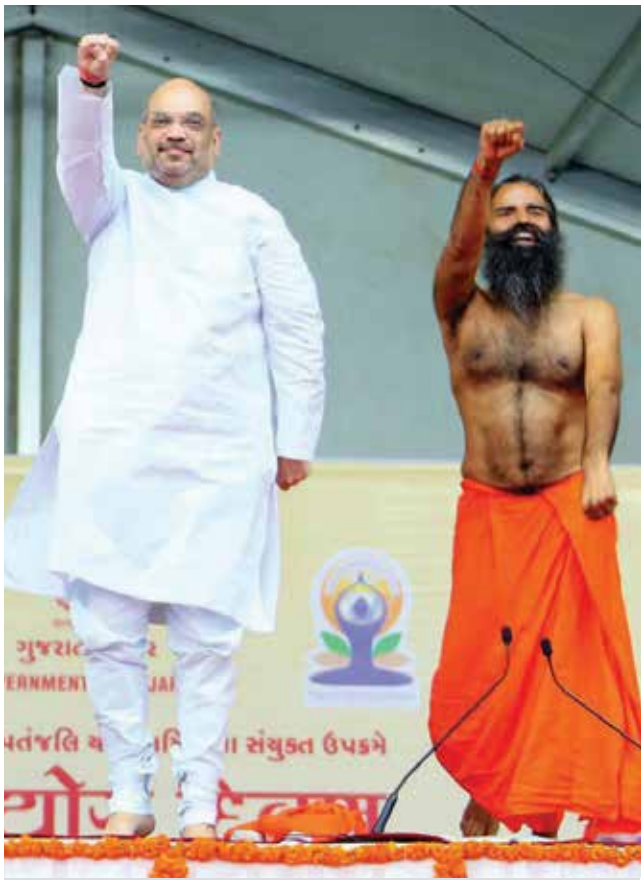

कनॉट प्लेस में समारोह का आयोजन आयुष मंत्रालय तथा नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने किया। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम सवेरे 6:15 बजे शुरू हुआ। 45 मिनट तक यानी 7:45 बजे पर विभिन्न योग आसन किए गए। हजारों लोगों के साथ श्री एम. वेंकैया नायडू, दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल, गोवा की राज्यपाल श्री मृदुला सिन्हा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद तथा युवा मामले व खेल राज्य मंत्री श्री विजय गोयल तथा संसद सदस्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने योग आसन किए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने स्कूली बच्चों के साथ योग किया। कोयंबटूर में ईशा योग सेंटर पर योग दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री महेश शर्मा, तमिलनाडु के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में योग के लिए भव्य आयोजन किया गया। यहां रायपुर में मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह ने योग किया। उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद थे। असम में मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनवाल ने योग किया। उनके साथ मंत्री श्री हेमंत बिस्वा और आचार्य बाल कृष्ण मौजूद थे।

गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री भी देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ तथा आईटीपीबी के इकाइयों की ओर से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आईटीपीबी कार्मियो ने लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई पर और सिंधु नदी के किनारे 11,600 फीट पर योगाभ्यास किया। लखनउ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सीएपीएफ के लगभग दो हजार कर्मी योगाभ्यास में शामिल हुए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिल्ली में 18 से 20 जून, 2017 तक आयोजित योग ओलंपियाड के विजेताओं की घोषणा की। योग ओलंपियाड का उद्देश्य योग के प्रति जागरुकता को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों, शिक्षकों तथा योग अभ्यास करने वालो का नेटवर्क बनाना है। पुरस्कार चार श्रेणियों में दिए गए। इसमें अपर प्राइमरी- लड़कियां तथा लड़के, माध्यमिक-लड़कियां तथा लड़के। प्रत्येक के लिए एक पुरस्कार शामिल है।

रक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में योग कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना की ओर से पहलगाम, श्रीनगर, करगिल, श्रीगंगानगर, नागपुर, लेह, बीदर, चेन्नई, बेंगलुरु, मंगलौर, डिब्रूगढ़, देहरादून, कोलकाता तथा अहमदनगर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रमादित्य, शिवालिक, कोमारता, ज्योति, आईएनएस जलश्व तथा आईएनएस क्रिच पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक बल ने आईसीजीएस सारथी और आईसीजीएस सम्राट पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया। नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों ने दिल्ली कैंट में डीजी एनसीसी शिविर में योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया।

दुनिया भर में योग दिवस की धूम

दुनिया भर में योग दिवस की धूम दिखी। पेरू में वर्ल्ड हेरिटेज साइट माचू पिच्चू पर भी योग किया गया। यहां माउंटेन पर चढ़ सैकड़ों लोगों ने योग किया। भारतीय समुदाय समेत बड़ी संख्या में लोगों ने तीसरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूत द्वारा आयोजित विशेष योग सत्रों में भाग लिया। वाणिज्यदूत रीवा गांगुली दास ने वाणिज्यदूत परिसरों में योग दिवस समारोहों के आयोजन का नेतृत्व किया और योग एवं आर्ट ऑफ लिविंग सत्रों में भाग लिया। दो घंटे चले योग एवं ध्यान शिविरों में भाग लेने आए लोगों को योग एवं ध्यान कराए जाने से पहले योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया गया।

यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने अपने विदेशी दूतावासों के माध्यम से अब्राहम लिंकन स्मारक, सिलवेन थियेटर वाशिंगटन डीसी, ला विलले पेरिस, फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण स्थानों, अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। विश्व के अनेक देशों में योग गुरु सेमिनार और चर्चाओं में शामिल हुए। ■

रामनाथ कोविंद बने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

बिहार के निवर्तमान राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। गत 19 जून को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संपन्न पार्टी संसदीय दल की बैठक में यह तय किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की।

बता दें कि पार्टी ने इससे पहले तीन सदस्यों की एक कमेटी गठित की थी जो सभी दलों से राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर चुकी है। इनमें गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू शामिल रहे।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जून है। 1 जुलाई तक नामांकन वापस लेने की तारीख है। उसके बाद 17 जुलाई को वोटिंग होगी और 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नव निर्वाचित राष्ट्रपति 25 जुलाई को पदभार संभालेंगे।

नामांकन दाखिल

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद ने 23 जून को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं डॉ. मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य कई नेता उपस्थित थे। राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री ईके पलानिसामी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि जदयू अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा बीजद प्रमुख एवं ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने भी समर्थन की घोषणा कर दी है। पर्चा दाखिला करने के बाद श्री कोविंद ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. कलाम आदि का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, 'मेरा हमेशा प्रयास होगा और मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए।' श्री कोविंद ने कहा कि कुछ ही सालों बाद देश आजादी के 75 साल सेलिब्रेट करने वाला है। ऐसे में वह भारत निर्माण के सपने के पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। श्री कोविंद ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और एनडीए के घटक दलों को भी धन्यवाद दिया। आखिर में कहा, 'सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा।' उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान में सभी दलों से वोट देने की अपील की।

श्री कोविंद के चार सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए। उनके प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख श्री प्रकाश सिंह बादल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू के नाम हैं। चार सेट के नामांकन पत्र में प्रत्येक में 60 प्रस्तावक और 60 समर्थक हैं।

राम नाथ कोविंद एक किसान के बेटे हैं, जो एक विनम्र पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और गरीब तथा वंचितों के लिए लगाया है। वे कानून की जानकारी रखने वालों के पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका ज्ञान और संविधान की समझ देश के लिए फायदेमंद होगा। उम्मीद है कि कोविंद अलग तरह के प्रेसिडेंट साबित होंगे। वे गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे।

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

रामनाथ जी हमेशा समाज, गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ जुड़े रहे हैं। एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं।

-अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से की मुलाकात

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद ने 22 जून को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इससे पूर्व उन्होंने 21 जून को भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की थी।

मोदी और शाह से मिले

श्री रामनाथ कोविंद ने 19 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद वे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। श्री कोविंद ने कहा कि वे समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे। ■

अपनी संस्कृति बनाए रखते हुए हम नवीन कार्यपद्धति का निर्माण करें : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय दौरे पर 8 जून को सुबह छत्तीसगढ़ पहुंचे। श्री शाह का मुख्यमंत्री डॉ. श्री रमन सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्री अनिल जैन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री सरोज पाण्डेय, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविचार नेताम, मंत्रीमंडल के सभी सदस्यगण, प्रदेश पदाधिकारी एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।

छत्तीसगढ़ प्रवास के पहले दिन श्री शाह ने कई संगठनात्मक बैठकें कीं और पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के भाजपा सांसदों, विधायकों, प्रदेश कार्यालय पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बैठक की एवं विभिन्न विषयों पर उनके साथ विचार-विमर्श किया।

संगठनात्मक बैठक के द्वितीय सत्र में श्री शाह ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों की संयुक्त बैठक की। श्री शाह ने जिलाध्यक्षों एवं प्रभारियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में हारे हुए मतदान केन्द्रों पर ध्यान केन्द्रित कर वहां नये सदस्य बनाने एवं उन बूथों का पृथक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर जनाधार बढ़ाने का निर्देश दिया।

भाजपा अध्यक्ष ने अपराह्न तीन बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक में कहा कि राजनीतिक कार्यों के साथ आप सभी को सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ हम संस्कारी एवं सशक्त भारत का निर्माण कर सकें।

19 विभागों व 10 प्रकल्पों की बैठक लेते हुए श्री शाह ने पार्टी पदाधिकारियों से कार्यालय का आधुनिकीकरण और हर कार्यालय में पुस्तकालय निर्माण की जरूरत पर बल दिया।

विशिष्ट और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की बैठक

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन 9 जून को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, मेकाहारा हॉस्पिटल, रायपुर में समाज के विशिष्ट और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की बैठक को संबोधित किया और उनसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और कार्यपद्धति का परिचय कराया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की 1950 से 2017 तक की यात्रा को मैं तीन हिस्सों में रखना चाहता

हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी मल्टीपार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसी भी पार्टी का मूल्यांकन तीन चीजों के आधार पर होना चाहिए - पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी का सिद्धांत और सत्ता में आने पर सरकार की कार्यपद्धति। श्री शाह ने कहा कि आज देश में लगभग 1650 छोटी-बड़ी पार्टियों में से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आतंरिक लोकतंत्र बचा हुआ है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के तीन साल पूरे हुए हैं, लेकिन इन तीन सालों में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाए, इसका प्रकार की पारदर्शी सरकार चलाने का काम मोदी जी ने किया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के विकास व गरीब-कल्याण के लिए लगभग 106 योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी एक वर्ग के लिए बनी हो।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की राजनीति को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को ख़त्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज एकजुट हुआ है, वे आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता का पूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी में है, उनके नेतृत्व में देश दिन दुगुना, रात चौगुना आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पीछे एकजुट हो देश के विकास के लिए अनवरत काम कर रही है। ■

'हमारे पांच साल का काम उनके 50 साल के काम पर भारी पड़ेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 21 जून को गुजरात के दो दिवसीय सांगठनिक प्रवास कार्यक्रम के दौरान हेलीपैड ग्राउंड, नडियाद में आयोजित सेन्ट्रल जोन के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को गुजरात से जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने सुबह जीएमडीसी ग्राउंड, अहमदाबाद में योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में बाबा रामदेव के साथ योग किया। इसके बाद उन्होंने नडियाद में खेडा जिला भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा अध्यक्ष आज भारत के लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान देसाई वागो, नडियाद गए और उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री शाह ने कहा कि मध्य गुजरात के आठ जिलों के 10,500 बूथों से लगभग सवा लाख पन्ना प्रमुख आज सरदार बल्लभभाई पटेल की जन्मभूमि पर, संतराम मंदिर की पवित्र धरती पर महाकाली के पावन सान्निध्य में बैठे हैं, हमारी विजय निश्चित है। उन्होंने कहा कि मीडिया को आज हमारे कार्यकर्ताओं के विराट दर्शन का फोटो प्रकाशित करनी चाहिए ताकि कांग्रेस सहित सभी को पता चले कि इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की भव्य विजय होने वाली है।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात में 1995 से निरंतर चली आ रही भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार, आनंदीबेन और विजय रुपानी सरकार, तीनों भाजपा सरकारों ने हमेशा जन-आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप ही काम किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 1995 से लेकर आज तक गुजरात में भाजपा कोई भी चुनाव हारी नहीं है चाहे वह विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोक सभा चुनाव। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि इस तरह जब हर कार्यकर्ता सम्मेलन में एक लाख से ज्यादा कार्यकर्ता एक साथ 'भारत माता की जय' का उद्घोष करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और गुजरात, दोनों जगह जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी गुजरात के मुख्यमंत्री चाहे वे श्री माधव सिंह सोलंकी हों या अमरसिंह चौधरी, जब राज्य में विकास कार्यों के लिए दिल्ली जाते थे तो उन्हें सात-सात दिन तक अप्वाइंटमेंट नहीं मिल पाता था और विकास कार्य रुका रह जाता था। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार ने गुजरात के विकास के लिए कई कार्य

किये हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय 13वें वित्त आयोग में गुजरात की सेन्ट्रल टैक्स में हिस्सेदारी 43,300 करोड़ थी, जो मोदी सरकार में 14वें वित्त आयोग में बढ़ कर 1,22,453 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि ग्रांट इन ऐड को भी 8,400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,79,62 करोड़ रुपये कर दिया गया है, इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट को भी 2,000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज ग्रांट के तौर पर कांग्रेस सरकार में 13वें वित्त आयोग में गुजरात को जहां केवल 2,723 करोड़ रुपये मिलते थे, अब 14वें वित्त आयोग में यह बढ़ कर 15,000 करोड़ रुपये हो गया है।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गुजरात में मुद्रा बैंक, शौचालय निर्माण और अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में तेज गति से कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन साल के शासनकाल में देश का मान-सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के विकास व गाँव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए 106 योजनाओं की शुरुआत की है ताकि समाज का कोई भी वर्ग विकास से अछूता न रहे। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विकास कार्यों के आधार पर बार-बार चुनकर सत्ता में आती है, इसी तरह गुजरात में भी हमें अभूतपूर्व जीत प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि जब श्री नरेन्द्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की 128 सीटें आई थीं, आज नरेन्द्र भाई देश के प्रधानमंत्री है, हमारी सीटें 150 से अधिक आनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि हम सब वोटिंग के दिन 12 बजे दोपहर से पहले मतदान करने का संकल्प लेकर और भाजपा की विचारधारा के साथ-साथ केंद्र की मोदी सरकार व गुजरात की विजयभाई रुपानी सरकार की उपलब्धियों का संदेश लेकर घर-घर जाएँ और तीन-चौथाई बहुमत के साथ गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध हों। ■

'मोदी सरकार ने गरीबों को देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय महाराष्ट्र प्रवास के दौरान 17 जून को मुंबई (महाराष्ट्र) के वसंत स्मृति में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं श्री देंवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले श्री शाह ने प्रदेश भाजपा कोर कमिटी और विभागों एवं प्रकल्पों की बैठक की।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तीन साल में कुछ ऐसे काम किये हैं, जो आज़ादी के बाद अब तक नहीं किये गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, शेयर बाजार भी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उन्होंने कहा कि 'एक देश, एक टैक्स' के स्वप्न को साकार करते हुए जीएसटी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास और आर्थिक सुधार के हर मोर्चे पर सरकार ने काफी बेहतर काम करके दिखाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 14वें वित्त आयोग के समय सेन्ट्रल टैक्स में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 74,104 करोड़ रुपये थी, जबकि मोदी सरकार में 15वें वित्त आयोग में यह 2,19,165 करोड़ रुपये हो गयी है। उन्होंने कहा कि ग्रांट इन ऐड के रूप में 14वें वित्त आयोग में महाराष्ट्र को 16,331 करोड़ रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 33,595 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट को भी 1835 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,140 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, लोकल बॉडीज ग्रांट को भी 8497 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 27,448 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र को 1,60,000 करोड़ रुपये की सहायता की गई है।

श्री शाह ने कहा कि महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु 26,000 करोड़ रुपये और 2015 के सूखे से निपटने के लिए अलग से 3,050 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि पहला 'मेक इन इंडिया' सप्ताह महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, जिससे राज्य को निवेश में काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक के लिए इंदु मिल की जमीन का हस्तांतरण किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के लिए भी भारत सरकार मदद कर रही है, मुंबई के कोस्टल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ट्रांस हार्बर लिंक - इन सभी परियोजनाओं के लिए भी भारत सरकार मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के

लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि मुंबई के अलावे शहरी विकास के लिए महाराष्ट्र को लगभग 63,523 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए हैं, जिसमें 7 स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत शहर और स्वच्छ भारत अभियान शामिल है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के लिए महाराष्ट्र को 20,100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि देश में अर्बन डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने जितने बजट का आवंटन किया है, उसका 15% अकेले महाराष्ट्र को देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि खदानों के आवंटन से प्राप्त राशि का एक लाभांश ट्राइबल के विकास के लिए देना तय किया गया है। उन्होंने कहा कि उदय योजना और स्वायल हेल्थ कार्ड के लिए भी महाराष्ट्र में काफी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देंवेंद्र फड़णवीस सरकार दोनों बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा की देवेंद्र फड़णवीस सरकार ने कई मोर्चों पर अच्छा काम करके दिखाया है, लेकिन कृषि विकास के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने अद्भुत सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर ग्रोथ जो पहले -8% था, उसमें 20% की बढ़ोत्तरी करने का काम राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जीडीपी के चारों सेगमेंट में सबसे कठिन एग्रीकल्चरल ग्रोथ ही होता है।

प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय महाराष्ट्र प्रवास के अंतिम दिन 18 जून को मुंबई (महाराष्ट्र) के बी जे हॉल में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों व पार्टी की विचारधारा पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले श्री शाह ने मुंबई के सह्याद्रि गेस्ट हाउस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष एवं कार्य विस्तारक योजना के तहत महाराष्ट्र में चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। ■

मंत्रिमंडल ने दी फसल ऋण पर ब्याज अनुदान को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को वर्ष 2017-18 के लिए किसानों के ब्याज हेतु अनुदान योजना (आईएसएस) को अपनी मंजूरी दे दी। इससे किसानों को केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के भीतर भुगतान योग्य अधिकतम 3 लाख रुपये तक की लघुकालिक फसल ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 20,339 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

अपनी निजी निधि के इस्तेमाल करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान योजना 1 वर्ष के लिए जारी रहेगी। नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन पर जोर देने के लिए किफायती दर पर लघुकालिक फसल ऋण के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराना है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) केंद्र सरकार वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम 1 वर्ष के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये के लघुकालिक फसल ऋण का समय पर भुगतान करने वाले सभी किसानों को प्रतिवर्ष 5% ब्याज अनुदान देगी। इस तरह किसानों को केवल 4% ब्याज देना होगा। यदि किसान समय पर लघुकालिक फसल ऋण का भुगतान नहीं करता है, तो वह उसे 2% ब्याज अनुदान ही मिलेगा।

ख) केंद्र सरकार वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज अनुदान के रूप में लगभग 20,339 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी।

ग) ऐसे लघु और सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के क्रम में, जिन्होंने अपने उत्पाद के फसल पश्चात भंडारण के लिए 9 प्रतिशत की दर पर कर्ज लिया है, केंद्र सरकार ने अधिकतम 6 माह के कर्जे के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान, यानी 7% की प्रभावी ब्याज दर को मंजूरी दी है।

घ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए भुगतान राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

ङ) यदि किसान समय पर लघुकालिक फसल ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो वह उपर्युक्त के स्थान पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे।

प्रमुख प्रभाव: कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादकता और कुल उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने में ऋण सुविधा एक महत्वपूर्ण घटक है। ब्याज अनुदान से उत्पन्न विभिन्न बाध्यताओं को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल की और से 20,339 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने से किसानों को लघुकालिक फसल ऋणों के साथ-साथ फसल–पश्चात भंडारण सुविधा को पूरा करके देश के किसानों को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा

करने में मदद मिलेगी। इस संस्थागत ऋण सुविधा से किसानों को गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों से कर्ज प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त करने में मदद मिलेगी, जहां से वह अत्यधिक दरों पर कर्ज लेने के लिए बाध्य है।

क्योंकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा फसल ऋणों की उपलब्धता से जुड़ी है, किसानों को फसल बीमा तक पहुंच कायम होने से उन्हें सरकार की दोनों किसान उन्मुखी पहलों से लाभ मिलेगा। बाजार में किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना उनके लिए लाभ सुनिश्चित करने के विचार से बाजार सुधार करना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में शुरु की गई इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का लक्ष्य किसानों को लाभांवित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना और एक प्रतिस्पर्धी तरीके से कीमत संबंधी खोज में समर्थ बनाना है। जबकि किसानों को ऑनलाइन व्यापार के लिए सलाह दी जाती है, ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण है कि उनके पास फसल पश्चात ऋण की उपलब्धता के भी विकल्प है, ताकि वे मान्यता प्राप्त भंडार गृहों में अपने उत्पादों का भंडारण कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड धारक लघु और सीमांत किसानों के लिए अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए ऐसे भंडारण पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान पर ऋण उपलब्ध है। इससे किसानों को बिक्री के लायक बाजार ढूंढ कर अपना उत्पाद बेचने और संकटापन्न विक्रय करने से बचने में मदद मिलेगी। इसलिए, लघु और सीमांत किसानों के लिए अपना किसान क्रेडिट कार्ड चालू रखना आवश्यक है।

किसानों की आय बढ़ाने के प्रति सरकार की गहरी रुचि है। इसके लिए सरकार ने बीज से लेकर विपणन तक कई नई पहले शुरू की है। संस्थागत स्रोतों से मिलने वाले कर्जे से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इनपुट प्रबंधन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम आदि सरकार की ऐसी सभी पहलों की प्रतिपूर्ति होगी।

पृष्ठभूमि: यह योजना वर्ष 2006-07 से चल रही है। इसके तहत, किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये का रियायती फसल ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। ■

मसाला निर्यात में अब तक की सबसे अधिक रिकॉर्ड 12 प्रतिशत की वृद्धि

दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई कड़े नियमों के लागू होने के बावजूद भारत के मसाला और मसालों से जुड़े पदार्थों के निर्यात में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई हैं। 2016-2017 में भारत ने 17664.61 करोड़ रूपये की कीमत के 94,7,790 टन मसालों का निर्यात किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मसालों की मांग बनी हुई हैं।

2015-2016 के दौरान 16238.23 करोड़ की लागत की 8,43,255 टन मात्रा का कुल निर्यात किया गया। जिसमें 12 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि दर रुपए के संदर्भ में 9 फीसदी तथा डालर के संदर्भ में 9 फीसदी रही। वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान भारत ने कुल 5,070.75 करोड़ रूपये की कीमत के 4,00,250 टन मिर्च का निर्यात किया। मिर्च के निर्यात में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मूल्य के मामले में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

मसालों में जीरा मिर्च के बाद सबसे अधिक निर्यात किये जाने वाला मसाला रहा। जीरे के निर्यात में मात्रा के लिहाज से 22 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मूल्य के हिसाब से इसमें 28 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई। भारत से 2016-2017 में 1963.00 करोड़ रूपये कीमत का 1,19,000 टन जीरा निर्यात किया गया।

भारत ने पहले के निर्यात रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपने मसालों की गुणवत्ता के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसालों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया। मसाला

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. ए.जयतिलक ने बताया कि कड़े खाद्य सुरक्षा मानकों के बावजूद निर्यात में वृद्धि सराहनीय है।

पिछले वर्ष की तुलना में जिस मसाले में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई वह सौंफ हैं। इसकी निर्यात मात्रा में इस वर्ष 129 फीसदी वृद्धि, जबकि कुल मूल्य में 89 फीसदी की वृद्धि हुई। लहसुन, जायफल, जावित्री, और अजवाइन जैसे मसालों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है।

डॉ. जयतिलक ने बताया कि मसाला बोर्ड के प्रयासों के चलते देश के प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक क्षेत्र उत्तर पूर्व में बड़ी इलायची के उत्पादन में वृद्धि हुई हैं और इसके निर्यात में 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। ■

अब डिजिटल रूप से सब्सक्राइब 'अटल पेंशन योजना'

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने "APY@eNPS" को शुरू कर दिया है, जिसमें सम्पूर्ण डिजिटल नामांकन प्रक्रिया शामिल है। अटल पेंशन योजना के विस्तार के लिए पीएफआरडीए ने जो विभिन्न कदम उठाये हैं, उसकी यह अद्यतन श्रेणी है। इसके तहत लोगों को ज्यादा आसानी होगी। पीएफआरडीए ने कोलकाता, बेंगलूरू और मुम्बई के बैंकों तथा डाक विभागों के साथ बैठकें की हैं।

पीएफआरडीए के सीजीएम श्री ए.जी.दास ने अभी हाल में मुम्बई में आयोजित एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें बैंकों और डाक विभागों के आईटी विभाग/नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीएफआरडीए ने सेवा प्रदाताओं को एपीवाई के अंतर्गत APY@eNPS के प्लेटफार्म की जानकारी दी। इस अवसर पर 45 से अधिक बैंक अधिकारी उपस्थित थे। एपीवाई सेवा प्रदाताओं को APY@eNPS के चैनल को 30 जून, 2017 के पहले विकसित करने के बारे में बताया गया।

एपीवाई को प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था और यह 01 जून, 2015 से चालू हो गई थी। एपीवाई 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। एपीवाई के अंतर्गत सभी सब्सक्राइबरों को 1,000 रूपये, 2,000 रूपये, 3,000 रूपये,4,000 रूपये और 5,000 रूपये की न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन 60 वर्ष की आयु से मिलेगी। यह पेंशन एपीवाई में शामिल होने के समय और उनके योगदान के अनुरूप होगी। एपीवाई सब्सक्राइबरों का आधार 54 लाख अधिक सब्सक्राइबरों का है। एपीवाई निजी प्रबंधकों ने 13.91 प्रतिशत का रिटर्न सृजित किया है। ■

बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून को कोच्चि मेट्रो का उद्घाटन किया और नई मेट्रो लाइन पर थोड़ी देर यात्रा की। बाद में उन्होंने राष्ट्र को कोच्चि मेट्रो समर्पित करने के लिए आयोजित एक समारोह में भारी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान मेरी सरकार ने देश के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। रेलवे, सड़क, बिजली हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र रहे हैं। प्रगति की बैठकों में मैंने व्यक्तिगत तौर पर आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक की 175 परियोजनाओं की समीक्षा की है। हमने बाधाओं को दूर किया है और इस क्षेत्रों में कार्यान्वयन की औसत दर में उल्लेखनीय सुधार किया है। अब हम अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे

पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स, डिजिटल और गैस शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से शहरों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार लाने के लिए हमने कई पहल की हैं। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया है। भारत में पचास शहर मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं। मेट्रो रेल व्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक लाभ जग-जाहिर हैं। हमने इस क्षेत्र में नीति तैयार करने को गति दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में भारत सरकार ने मेट्रो रेल के रोलिंग स्टॉक और सिग्नल प्रणाली के लिए विनिर्देशों को मानकीकृत किया है। यह विनिर्माताओं को भारत के लंबी अवधि के लिए विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 'मेक इन इंडिया' दृष्टि के अनुरूप मेट्रो रोलिंग स्टॉक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आम लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने और भूमि के उपयोग एवं परिवहन को एकीकृत करते हुए शहरी नियोजन में एक उल्लेखनीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भारत सरकार ने अप्रैल 2017 में एक नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी जारी की। यह नीति शहरों को ट्रांजिट पर निर्भर होने के बजाय ट्रांजिट केंद्रित के तौर पर बदलना चाहती है। इसका उद्देश्य कम से कम चलने वाला समुदाय सृजित करना और सार्वजनिक परिवहन को ट्रांजिट के करीब लाना है। मैं वैल्यू कैप्चर फाइनैंस पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए वेंकैया जी के नेतृत्व में शहरी विकास मंत्रालय की सराहना करता हूं। यह बढ़ते भूमि मूल्य कब्जे में लेने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

साथ ही श्री मोदी ने यह भी कहा कि अरब सागर की रानी कोच्चि मसालों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आज इसे केरल की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। केरल आने वाले घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या के लिहाज से कोच्चि पहले स्थान पर है। इसलिए यह उचित है कि कोच्चि में मेट्रो रेल की सुविधा होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है और 2021 तक इसे 23 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए शहरी बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए एक व्यापक द्रुत परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। यह कोच्चि के आर्थिक विकास में भी योगदान करेगा।

उन्होंने कहा कि कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड भारत सरकार और केरल सरकार की 50:50 का संयुक्त उद्यम है। कोच्चि मेट्रो के लिए केंद्र सरकार ने अब तक दो हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। आज उद्घाटन होने वाला चरण अलुवा से पलारिवट्टम तक परिचालन करेगा। यह 13.26 किलोमीटर की दूरी और ग्यारह स्टेशनों को कवर करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आधुनिक सिग्नल प्रणाली, जिसे 'कम्युनिकेशंस बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नेलिंग सिस्टम' कहा जाता है, के साथ चालू होने वाली पहली मेट्रो परियोजना है। इसके डिब्बे 'मेक इन इंडिया' दृष्टि को दर्शाते हैं। इन डिब्बों को फ्रांस की कंपनी अल्सटॉम द्वारा चेन्नई के समीप उसके कारखाने में निर्मित किया गया है और इसमें करीब 70 प्रतिशत भारतीय उपकरण लगाए गए हैं। ■

लोकसभा में विरोधी पक्ष के प्रमुख नेता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी

| दीनदयाल उपाध्याय |

भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और लोकसभा में विरोधी पक्ष के प्रमुख नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी वाग्मिता और विद्वत्ता और महान् व्यक्तित्व के कारण लोकप्रिय हैं।

'नाभिषेको न संस्कारः
सिंहस्य क्रियते मृगैः।
विक्रमोर्जितराज्यस्य
स्वयमेव मृगेन्द्रता।।'

(नारायण पंडित हितोपदेश १/19)

सिंह का कभी राज्याभिषेक नहीं होता, अपितु अपने पराक्रम से वह स्वतः ही 'मृगेंद्र' पद को प्राप्त करता है। कवि की यह उक्ति वन के प्राणियों के लिए ही नहीं, मानव के व्यवहार में भी चरितार्थ होती है। संसद में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की स्थिति इसका उदाहरण है। अध्यक्ष मावलंकर द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार श्यामाप्रसाद चाहे विरोधी दल के नेता न स्वीकृत हों, किंतु संसद के सभी सदस्य, यहाँ तक कि उनके विरोधी दल के सदस्य भी उन्हें संसद के विरोधी दल का ही नहीं, अपितु अपना नेता भी मानते हैं और वैसे तो संसद में प्रतिदिन छह घंटे भाषण ही होते रहते हैं। और अखबारों में अनेक सदस्यों के भाषण भी छपते हैं, किंतु एक ही व्यक्ति ऐसा है, जिसका भाषण सुनने के लिए प्रत्येक सदस्य लालायित रहता है। क्या विरोधी दल के और क्या कांग्रेस के, सभी सदस्य उस समय अपनी सीटों पर दिखाई देंगे, जब श्यामाप्रसाद मुखर्जी अपना भाषण प्रारंभ करते हैं। दर्शकों मे गैलरी खचाखच भरी रहती है तथा प्रेस रिपोर्टर, चाहे वे भाषण को अखबारों में न छापें, एक-एक शब्द को लेखनीबद्ध करने के लिए आतुर रहते हैं। कारण, श्यामाप्रसाद मुखर्जी के शब्दों में वकील का तर्क ही नहीं, कवि का हृदय भी रहता है। स्वर्ग से गिरने वाली ओस की बूँदों के समान कभी उनके शब्द सरलता से हृदयंगम होते जाते हैं, तो कभी उनकी दहाड़ से विरोधियों के छक्के छूट जाते हैं। कांग्रेस के लोग उनके शब्दों की क़ीमत करते हैं, क्योंकि वे उनके हृदय की भाषा में बोलते हैं। अपने जिन भावों को नेहरूजी की भृकुटी के भय से तथा अनुशासन के ताले के कारण वे प्रकट नहीं कर पाते, उन्हें जब वे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के भाषण में पाते हैं तो बरबस उनका हृदय उनकी ओर खिंच आता है। एकांत में वे उनकी सराहना करते हैं, पर संसद में आत्मप्रवंचना के अलावा और सहारा ही क्या हैं।

डॉ. मुखर्जी कभी विरोध के लिए विरोध, अथवा बोलने के लिए बोलने की नीति में विश्वास नहीं करते। वे अपने विषय के साथ जब एकात्मता का अनुभव करते हैं, तब बोलते हैं और वही बोलते

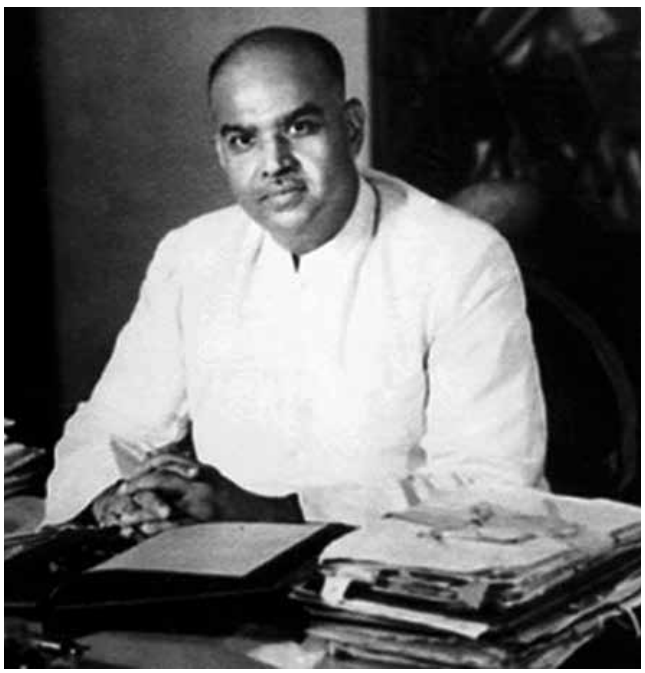

हैं, जिसे वे अनुभव करते हैं। हृदय की सच्ची अनुभूति ही तो काव्य है। इस काव्य के अक्षर स्वतः अभिमंत्रित हो जाते हैं। उनका असर केवल संसद में ही नहीं बल्कि संसद के बाहर कोटि-कोटि हृदयों तक पहुँचता है। देश की भूखी, नंगी, पीड़ित, त्रस्त और अज्ञानांधकार में आवृत्त जनता उन्हें जाने या न जाने, उनके कानों तक उनका नाम चाहे न पहुँचा हो, किंतु उनकी मूक भावनाओं को वाणी का परिधान डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ही पहनाते हैं।

कम्युनिस्टों के समान वे मजमेबाजो की सस्ती वक्तृत्व कला में विश्वास नहीं करते और न संसदीय शिष्टाचार की अवहेलना का बेसुरा राग अलापना ही उन्हें पसंद है। संसद ने यदि भाषणों को निश्चित समय की सीमा में बाँधा हो तो न तो उन्होंने सीमोल्लंघन का कभी प्रयत्न किया और न कोई ऐसा विषय ही छूटा, जिसे वे प्रस्तुत करना चाहते हों और न कर पाए हों। 'मात्रालाघवेन पुत्रोत्सव मिति वैयाकरणः मन्यनो' के अनुसार उन्होंने भाषण को प्रयत्नपूर्वक कभी संक्षिप्त भले न किया हो, किंतु गागर में सागर भर देने की कला सिद्ध है और फिर सागर के सभी रत्न भी उस गागर में समा जाते हैं।

डॉ. मुखर्जी की आलोचना रचनात्मक होती है। उनके सुझाव

विचारपूर्ण होते हैं। किंतु उनका व्यंग्य भी हृदय को विदीर्ण करने वाला होता है। यद्यपि उसमें शत्रु के प्रति विद्वेष का भाव नहीं रहता। उनके एक-एक शब्द में सरकार को चुनौती रहती है। उनके तथ्यों को यदि किसी ने चुनौती दी तो वे कभी बगलें नहीं झांकते और न भविष्य में

हाज़िरजवाबी भी उनका ऐसा गुण है, जो मौक़े पर उनके बड़े काम आता है। डॉ. मुखर्जी के भाषण से परेशान हो एक बार नेहरू जी कह उठे, ''मालूम होता है, डॉ. मुखर्जी की संगत ठीक नहीं है।'' ''जी, हां'' मुखर्जी बोल उठे, ''आपके साथ ढाई वर्ष रह चुका हूँ।'' नेहरू जी को ठीक से जवाब देते नहीं बना, किंतु संसद के सभी सदस्य मुसकरा उठे।

प्रमाण प्रस्तुत कर अपनी बात सिद्ध करने का वादा करते हैं। वे इन प्रमाणों को पहले से अपने पास तैयार रखते हैं तथा आवश्यकता हुई तो प्रस्तुत भी कर देते हैं। हाल ही में कश्मीर के संबंध में भाषण करते हुए शेख अब्दुल्ला की सांप्रदायिक नीति की वे निंदा कर रहे थे तो कश्मीर के एक सदस्य ने टोक दिया कि वे कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर में सांप्रदायिकता ज़िंदा है। डॉ. मुखर्जी ने तत्काल जेब से एक पुस्तिका निकाली, जो कश्मीर सरकार की छापी हुई थी और उसके उद्धरणों से अपनी उक्ति की प्रामाणिकता सिद्ध की।

हाज़िरजवाबी भी उनका ऐसा गुण है, जो मौक़े पर उनके बड़े काम आता है। डॉ. मुखर्जी के भाषण से परेशान हो एक बार नेहरूजी कह उठे, ''मालूम होता है, डॉ. मुखर्जी की संगत ठीक नहीं है।'' ''जी, हां'' मुखर्जी बोल उठे, ''आपके साथ ढाई वर्ष रह चुका हूँ।'' नेहरूजी को ठीक से जवाब देते नहीं बना, किंतु संसद के सभी सदस्य मुसकरा उठे।

संसद में सभी विरोधी दल के सदस्य उनसे बराबर परामर्श लेते रहते हैं और उन्होंने कभी किसी को सत्परामर्श से वंचित नहीं रखा। अनेक दल चाहते हैं कि वे उनके साथ मिलकर काम करें तथा एक विरोधी दल बना लें, किंतु वे ऐसा कोई दल संगठित नहीं करना चाहते, जिसका कोई सैद्धांतिक आधार न हो। केवल नेतृत्व के लिए सिद्धांतों से समझौता करने को वे तैयार नहीं और यही कारण है कि उनके राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक दल में अभी 34 सदस्य हो पाए हैं। उनका विश्वास है कि यदि वे सिद्धांत पर डटे रहे तो अवश्य ही उनके दल की संख्या बढ़ेगी और इसलिए सिद्धांतहीन सौदेबाजी के आधार पर अपने दल को बढ़ाने को अग्रसर होने की अपेक्षा वे थोड़े ही लोगों से संतुष्ट हैं। दल में अन्य लोग आएं या न आएँ किंतु उन्हें सब विरोधी दल के नेता स्वीकार करते हैं। देश भी आज उनकी ओर इसी नाते से देखता है और यह विश्वास है कि संसदीय क्षेत्र में पंडित नेहरू के बाद वे ही दूसरा नेतृत्व निर्माण करने में सफल होंगे। ■

- पांचजन्य, जुलाई 7, 1952

प्रधानमंत्री ने स्वामी आत्मस्थानंदजी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रामकृष्ण मठ एवं मिशन के प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'स्वामी आत्मस्थानंद जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं अपने जीवन के काफी महत्वपूर्ण काल के दौरान उनके साथ रहा था।

स्वामी आत्मस्थानंद जी अपार ज्ञान और पांडित्य से ओतप्रोत थे। उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। जब कभी मैं कोलकाता का दौरा करूंगा, मुझे हमेशा स्वामी आत्मस्थानंद जी के आशीर्वाद की तलाश रहेगी। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष के रूप में स्वामी आत्मस्थानंद जी ने अथक काम किया और इसके प्रभाव को वैश्विक स्तर पर फैलाया।'

गौरतलब है कि स्वामी आत्मास्थानंद महाराज का 18 जून को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 99 वर्ष के थे। उन्होंने कोलकाता स्थित रामकृष्ण मिशनसेवा प्रतिष्ठान में आखिरी सांस ली। ■

स्वामी विवेकानंद

(12 जनवरी 1863 – 4 जुलाई 1902)

स्वामी विवेकानन्द का वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। वे वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो नगर में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासम्मेलन में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदान्त अमेरिका और यूरोप के हर-एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। अपने मत से पूरे विश्व को हिला देने की शक्ति थी उनमें। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कलकत्ता (कोलकता) में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक व सामाजिक विषयों में व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। भुवनेश्वरी देवी सरल व अत्यंत धार्मिक महिला थीं।

वास्तविक भारत की खोज

भारत यात्रा के दौरान घोर गरीबी तथा पिछड़ापन देखकर स्वामी विवकानंद काफी द्रवित हुए। वे पहले धार्मिक संत थे, जिन्होंने खुलेतौर पर कहा कि भारत के पतन का प्रमुख कारण आम जन की उपेक्षा है। लाखों-करोड़ों भूखे लोगों को भोजन और जीवन की अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराना सर्वाधिक जरूरी है। इसके लिए जनता को कृषि एवं ग्राम उद्योग आदि में उन्नत तरीकों का उपयोग दरअसल सीखाना होगा।

स्वामी विवकानंद ने गरीबी के मुख्य कारण को समझा, जो उनके समकालीन दूसरे समाज सुधारक नहीं समझ पाए। यही कारण था कि सैकड़ों वर्ष के शोषण के कारण पिछड़े हुए लोगों का विश्वास अपनी क्षमता से उठ चुका था। सबसे पहली जरूरत उन्हें स्वयं पर विश्वास करने की है। इसके लिए उन्हें जीवनदायी एवं प्रेरणादायी संदेश की जरूरत है। स्वामी विवकानंद ने आत्मा के सिद्धांत में इस संदेश को प्राप्त किया।

उन्होंने देखा कि घोर गरीबी के बावजूद लोग अपने धर्म से जुड़े रहे, परंतु उन्हें कभी भी वेदांत की जीवनदायी सिद्धांतों नहीं बताया गया। स्वामी विवकानंद ने कहा कि जनता को दो तरह के ज्ञान की आवश्यकता है-सांसारिक ज्ञान, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे उनका आत्मविश्वास मजबूत हो। प्रश्न यह था कि इन दो प्रकार के ज्ञान का प्रसार कैसे हो। स्वामी जी ने इसका उत्तर शिक्षा के विकास में पाया।

देशवासियों में जागरण

स्वामी जी जनवरी 1897 में अमेरिका से भारत वापस लौटे। अपने उत्साहपूर्व स्वागत के बीच उन्होंने देश के विभिन्न भागों में अनेक भाषण दिए, जिससे देश में एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। इन भाषणों के माध्यम से उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख कार्य करने का प्रयास किया।

1-लोगों में धार्मिक चेतना भरना तथा उनमें अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व जागृति करना।

2-हिंदू धर्म का विभिन्न संप्रदायों के बीच समान सिद्धांतों के आधार पर एकीकरण करना।

3-शिक्षित लोगों का ध्यान पिछड़ी जनता की बदहाली पर केंद्रित करना तथा उनके विकास के लिए वेदांत के सिद्धांत को व्यवहार में लाना।

भारत में स्वामीजी का योगदान

भारत में मौजूद भाषायी, जातीय, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विभिन्नता के बावजूद देश की सांस्कृतिक एकता हजारों सालों से एक बनी हुई थी। इस तथ्य को स्वामी विवेकानंद भली-भांति महसूस किया और उन्होंने भारत संस्कृति के मूलभूत आधारों की पहचान की और उन्होंने बड़े प्रभावशाली व स्पष्ट ढंग से राष्ट्र की एकता में इसके महत्व को परिभाषित किया।

स्वामीजी ने देशवासियों को भारत की महान आध्यात्मिक धरोहर को सही तरीके से समझाया और उन्हें अपने अतीत पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की खामियों से भी देशवासियों को आगाह किया और उनकी कमियों को दूर करने के लिए भारत के योगदान पर चर्चा की।

एकता का भाव, अपने अतीत पर गर्व और लक्ष्य के प्रति समर्पण आदि ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई महान नेताओं ने स्वामी जी के योगदान को काफी सराहा। नेता सुभाष चंद्र बोस ने लिखा-'स्वामी जी ने पूर्व तथा पश्चिम, धर्म तथा विज्ञान, अतीत व वर्तमान के बीच संतुलन स्थापित किया और इसलिए वे महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनके शिक्षा से अभूतपूर्व आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास प्राप्त किया।'

जीवन के अन्तिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा- ''एक और विवेकानन्द चाहिये, यह समझने के लिये कि इस विवेकानन्द ने अब तक क्या किया है।'' जीवन के अन्तिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः दो तीन घण्टे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही महासमाधि ले ली। ■

भाजपा ने रचा इतिहास, 17 सीटों पर दर्ज की जीत

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बीते तीन दशक में पहली बार शिमला नगर निगम में सर्वाधिक सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। पार्टी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, निगम पर 26 वर्षों तक काबिज रहने वाली कांग्रेस के 12 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। साथ ही चार निर्दलीय तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का एक उम्मीदवार भी चुनाव जीतने में कामयाब रहा।

गौरतलब है कि मतदान 16 जून को हुआ था, जिसमें 91,000 से भी अधिक योग्य मतदाताओं में से करीब 58 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव में निर्वासित तिब्बतियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चेन्नई तथा कोलकाता के बाद शिमला सबसे पुराना नगर निगम है।

चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच था। हालांकि उम्मीदवारों ने पार्टी के चुनाव चिन्हों पर चुनाव नहीं लड़ा। भाजपा ने 34 उम्मीदवारों, कांग्रेस ने 27 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने 22 उम्मीदवारों का समर्थन किया था।

नगर निगम शिमला के चुनाव पहले 1986 में हुआ था। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही शिमला नगर निगम के चुनाव करवाए गए थे। इसके बाद से लगातार 2012 तक कांग्रेस का ही राज रहा। कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर रहे। 2012 में पहली बार नगर निगम शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव डायरेक्ट करवाए, इसमें माकपा के मेयर और डिप्टी मेयर जीते। पहली बार भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर बनाने का मौका मिला है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

"शिमला नगर निगम में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, फिर से विकास की राजनीति में लोगों की आस्था को दर्शाता है।"

"मैं भाजपा को समर्थन के लिए शिमला के लोगों को धन्यवाद देता हूं और भाजपा हिमाचल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई देता हूं।"

अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

"शिमला नगर पालिका चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। मैं सतपाल सत्ती और भाजपा हिमाचल इकाई के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।"

"भाजपा पर विश्वास के लिए शिमला की जनता का आभार। परिणाम राज्य की जनता के मूड के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास की राजनीति में जनता के विश्वास को दर्शाते हैं।"

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला की जनता को बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को नगर निगम बनाने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि अब भाजपा वह कार्य करके दिखाएगी जो कांग्रेस पिछले कई सालों से नहीं कर पाई। इस जीत से भाजपा नेताओं तथा शिमला की जनता को यह यकीन हो गया है कि अब प्रदेश में फिर से भाजपा राज करेगी तथा कांग्रेस को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी।

वहीं, निगम चुनाव में जीत के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि इस चुनाव परिणाम ने विधानसभा चुनाव की इबारत साफ लिख दी है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी।

शिमला में पहली बार भाजपा के महापौर, उप महापौर

नगर निगम शिमला में 20 जून को 31 साल बाद भाजपा ने महापौर व उप महापौर पद पर जीत हासिल की। कुसुम सदरेट (35) नगर निगम के इतिहास में पहली बार सबसे युवा महापौर चुनी गईं। वहीं, राकेश कुमार उप महापौर बने। ये दोनों पहली बार पार्षद बनकर पहली बार महापौर व उप महापौर बने। ढाई साल बाद दोबारा दोनों पदों के लिए नए उम्मीदवार चुने जाएंगे। ■

अद्भुत 3 साल, 3 गुना महिला विकास

डॉ. सुधा मलैया

मोदी सरकार के 3 साल सही में बेमिसाल हैं। अनेक अर्थों में स्वतंत्रता के बाद के दशकों में महिलाओं ने हर दिशा में और हर क्षेत्र में अपने कदमों के निशान छोड़े हैं, ऊंचाइयों को छुआ है किंतु न उसकी यातनाओं में कमी आई और न समस्याएं घटी। देवी जैसे सम्मानित होने के बावजूद बार-बार अपमानित होती रही है। अधिकार दिए गए हैं किंतु दूसरे दरवाजे से छीन लिए जाते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हर महिला की कमोबेश यही कहानी है। वह उसी प्रकार उपेक्षिता है।

किन्तु अब एक सामान्य भारतीय ग्रहणी के घर संसार की मूल आवश्यक्ताओं की ओर जिस प्रकार मोदी सरकार ने ध्यान दिया है वह तारीफ के काबिल है। एक आम स्त्री की दुनिया रसोई से शुरू होती है और वही समाप्त होती है। इससे पहले अटल जी की सरकार ने गैस सिलेंडरों की कालाबाज़ारी पर रोक लगाई थी और अब पहली बार ढाई करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को फ्री गैस गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इससे उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है, कितना उनके जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ है यह कहने की बात नहीं है। इस एक योजना से ही न जाने कितनी महिलाओं का आकाश उजला-उजला हो गया है....

उफ़क के दरीचे से किरणों ने झांका
फजा तन गई रास्ते गुनगुनाए
सिमटने लगी नर्म कोहरे की चादर
जवां शाखसारों ने घूंघट उठाये

जब वन ही खत्म होते जा रहे हैं और और गांवों में जलाऊ लकड़ी का लगभग अकाल पड़ गया है। ऐसे में गांव गांव की महिलाएं कहां से ईधन लाएं और किस पर रोटी बनाएं। इस समस्या की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। कनेक्शन ही नहीं था तो गैस का चूल्हा भी कहां से लाएं। जब कनेक्शन दे दिए गए तो गैस एजेंसी भी खुली, रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। वहीं देश की लाखों महिलाओं को चूल्हा फूंकने और आंखों की रोशनी चले जाने के डर से मुक्ति मिली।

इसी तरह नौकरी पेशा लाखों महिलाओं को मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक से राहत मिली है। 3 महीने के बच्चे को घर में घर में छोड़कर नौकरी पर जाना कठिन होता है, इसीलिये 12 सप्ताह का अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह का करना सुखद पहल है। साथ ही सरोगेट माता के लिए 12 सप्ताह का अवकाश। बच्चे को गोद लेने वाली महिला के लिए रोजगार प्रदाता और कामगार के आपसी रजामंदी से घर में काम करने की सुविधा प्रदान की गई की गई है।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत बेटियों की लगातार गिरती जनसंख्या से चिंतित सरकार की कोशिश से महत्वपूर्ण परिणाम आए हैं। हजार लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 912 से बढ़कर 919 पर पहुंच गयी है। अनुपात की दृष्टि से सबसे बुरे राज्य हरियाणा में 2000 से 2006 तक जो संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 762 थी अब वह 846 हो गई है। असम में भी यह अनुपात 794 से बढ़कर 996 पर पहुंच गया है।

सुना है कि मौसम बदलने लगा है,
मैंने उसे छू दिया था वह मेरे साथ चलने लगा है।

देश का बदलता मानस शीतल पवन का झोंका है। इसीलिए बालिकाओं के सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई सुकन्या योजना के अंतर्गत उनकी संपूर्ण शिक्षा और 18 वर्ष का होने पर शादी में मिले व्यवहार के छोटे निवेश पर ज्यादा ब्याज दर और ज्यादा कर्ज पर कम ब्याज की व्यवस्था है। 2 दिसंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2016 तक इस योजना के तहत 9996085 खाते खोले जा चुके हैं और इसमें 9455.30 करोड़ों रुपए जमा हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के तहत 3 से 6 महीने की गर्भवती महिला को गर्भस्थ शिशु सहित निशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। बच्चे अधिक से अधिक स्वस्थ हों और माताएं उन्हें स्तनपान कराएं। देश के सभी जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम का लाभ का विस्तार हो, इसकी घोषणा 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। 1 जनवरी 2017 से लागू इस योजना के अंतर्गत लगभग 51.70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। देश के 53 जिलों में इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पहले 4000 रूपये दिए जा रहे थे, अब वह राशि 6000 रूपये तक बढ़ा दी गई है और देश के सभी 665 जिलों में अब यह लागू है।

जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय महिला सुरक्षा एक ज्वलंत मुद्दा था, निर्भया कांड होकर ही चुका था, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा हो जिससे वह कभी भी संकट में रहें तो अपनी सूचना घर और जरूरी नंबरों पर दे सकें। इस दृष्टि से भविष्य में नए बनने वाले स्मार्ट फोन में पैनिक बटन की सुविधा

सुनिश्चित की गयी है। स्मार्ट मोबाइल फोनों में 5 व 9 नंबर का बटन इसके लिए इसके लिए सुनिश्चित किया है। 1 जनवरी 2018 से सब मोबाइल फोनों में GPS की सुविधा अनिवार्य होगी। पैनिक बटन सीधे 112 नंबर से जुड़कर सहायता उपलब्ध कराएगा। इसी प्रकार महिला हेल्पलाइन योजना में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए 24 घंटे आपातकालीन और तत्काल सहायता दी जा सकेगी।

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी के लिए भी बाल श्रम निषेध एवं नियमन विधायक पारित किया गया है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराने पर पाबंदी और सज़ा का प्रावधान है। हालांकि वह अपने परिवार का हाथ उन कामों में बंटा सकते हैं जो खतरनाक नहीं हैं। इससे बालक और बालिकाओं की शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हो सकेगी। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को कुछ शर्त के साथ कम खतरनाक काम धंधों में लगने की अनुमति मिलेगी।

इसी तरह सुरक्षा बंधन योजना भी सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम प्रदान करती है, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आठ प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है, यह योजना भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लाभान्वित कर रही है, क्योंकि उनके हाथ में आर्थिक शक्ति आई है। वह बड़ी ब्याज पर निवेश कर सकती हैं। योजना में 1 मार्च 2017 तक कुल 133,854,778 इनरॉलमेंट हो चुके थे। इसमें से अटल पेंशन योजना में 3,790,996 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 30,888,908 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 99,174,874 इनरॉलमेंट शामिल है।

और भी बहुत से योजनाएं महिलाओं के जीवन में रोशनी की किरण की तरह हैं। गरीब की हालत सुधरती है तो महिलाओं की तकलीफ और घुटन स्वतः ही कम ही जाती है। 3 साल में तीन गुना महिला विकास अद्भुत है। ■

(लेखिका भाजपा राष्ट्रीय प्रकाशन विभाग की सदस्या हैं)

वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक 2017 के पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान से जुड़े प्रावधान उपलब्ध होंगे।

वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 के लागू होने पर एक समाधान निगम की स्थापना हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। इससे इस विधेयक की अनुसूचियों में सूचीबद्ध क्षेत्रवार अधिनियम के समाधान संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने अथवा संशोधित करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरुप जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को समाप्त करने से लेकर जमा राशि बीमा अधिकारों के स्थानांतरण और समाधान निगम के प्रति उत्तरदायित्व कायम करना भी संभव होगा।

समाधान निगम वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व और दृढ़ता का संरक्षण करेगा और एक तर्कसंगत सीमा तक बाध्यताओं के दायरे में उपभोक्ताओं का संरक्षण करेगा तथा एक संभव सीमा तक लोगों के धन का भी संरक्षण करेगा।

सरकार ने हाल में गैर वित्तीय संस्थाओं के तरलता समाधान के लिए तरलता और दिवालियापन संहिता, 2016 (कोड) को लागू किया है। प्रस्तावित विधेयक वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समाधान कार्यक्रम प्रस्तुत करके कोड के प्रतिपूरक की भूमिका निभाता है। इसके लागू हो जाने पर कोड के साथ यह विधेयक अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक समाधान आधारित कार्यक्रम उपलब्ध करेगा।

वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 का लक्ष्य वित्तीय तौर पर खस्ताहाल वित्तीय सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को राहत देना है। खस्ताहाल कारोबारों को बचाने के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को सीमित करके वित्तीय संकट के समय में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच अनुशासन स्थापित करना भी इसका लक्ष्य है।

दूसरी ओर, संकट के समय आवश्यक औजार उपलब्ध कराकर, पर्याप्त रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थायित्व कायम रखने में मदद मिलेगी। इस विधेयक का लक्ष्य बड़ी संख्या में खुदरा जमाकर्ताओं के लाभ के लिए जमाराशि बीमा के मौजूदा ढांचे को सशक्त और सुसंगत बनाना है। इसके अलावा, इस विधेयक के माध्यम से खस्ताहाल वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं के निदान के लिए लगने वाले समय और धन में कमी लाना भी इसका लक्ष्य है। ■

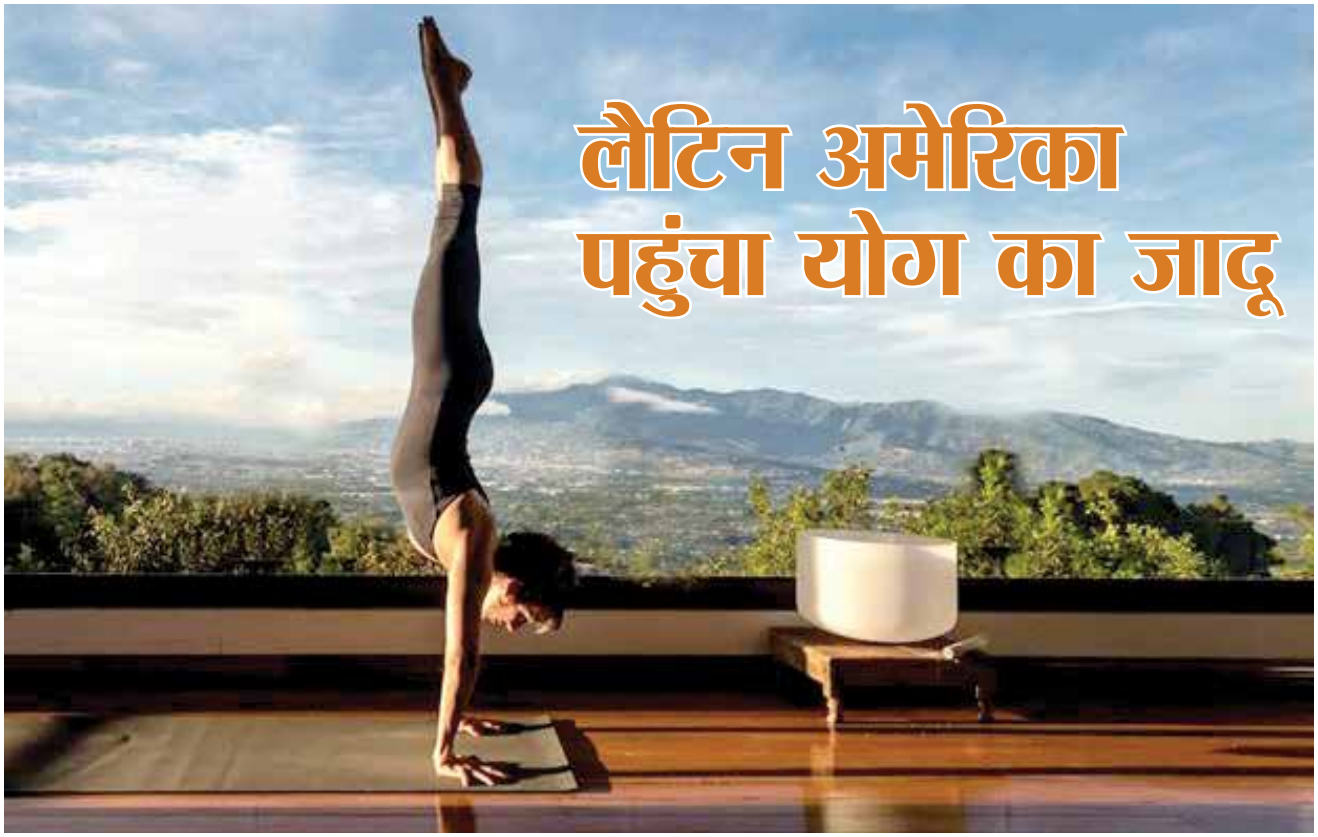

लैटिन अमेरिका पहुंचा योग का जादू

हुमा सिद्दिकी

अपनी अंतरात्मा में स्वयं को महसूस करने से बेहतर कोई अनुभव नहीं है। सदियों से योग अंतर्मन की शांति जागृत करने के लिए जाना जाता है। हम अकसर मन की शांति की तलाश भौतिक वस्तुओं में करते हैं।

आश्चर्य नहीं कि लैटिन अमेरिकी इस शानदार विज्ञान की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वास्तव में वे भारत को योग, ध्यान, दर्शन, ज्ञान, संस्कृति तथा अध्यात्मवाद की भूमि मानते हैं। पूरे लैटिन अमेरिका में योग विद्यालयों का दिखाई पड़ना एक आम बात है। कुछ लैटिन अमेरिकी जेलों में अपराधियों को योग और ध्यान सिखाया जाता है। मीलों तक अछूती प्राकृतिक बस्तियों और माया तथा इंकान सभ्यताओं की गहन आध्यात्मिक परंपराओं वाले मध्य तथा दक्षिण अमेरिका, आध्यात्मिक यात्रा के लिए उत्तम स्थान है।

यद्यपि कई वर्षों से इस क्षेत्र में योग का अभ्यास किया जाता रहा है तथापि पिछले दो वर्षों में योग की इच्छा रखने वालों में एक 'विस्फोट'-सा हुआ है तथा भारतीय संस्कृति के प्रति तेजी से रूचि बढ़ी है। अब योग का पेरू, बोलिविया तथा लैटिन अमेरिका के आस-पास के भागों में लोकप्रिय होना निश्चित है, क्योंकि इस संबंध में हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। पेरू की राजधानी लीमा में भारतीय दूतावास ने आयुष मंत्रालय के निवेदन से भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूलसीआई) द्वारा विकसित योग पेशेवरों के मूल्यांकन तथा प्रमाणन के लिए स्वैच्छिक योजनाओं को बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है।

आश्चर्य की बात नहीं कि लैटिन अमेरिका उन योग उत्साहियों के लिए एक पंसदीदा गंतव्य है जो अपने योग अनुभवों को और बेहतर बनाने की तलाश में है। इस क्षेत्र में विकल्पों की कोई कमी नहीं है। कोस्टारिका, निकारागुआ, पेरू, ब्राजील, होंडुरास, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, इक्वाडोर, चिली सहित सभी देश योग उत्साहियों की पंसदीदा स्थलों में से हैं।

एक छोटे देश कोस्टारिका की पचास लाख जनसंख्या में दो सौ भारतीय हैं, परंतु इन दो सौ लोगों ने बहुत उत्साह से कोस्टारिका की अधिकांश जनसंख्या को सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक कारणों से भारत की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है। कोस्टारिका को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांति तथा आर्थिक स्थायित्व के लिए मध्य अमेरिका में एक रत्न के रूप में जाना जाता है। यहां स्वास्थ्य जीवन-शैली अपनाने वालों की संख्याएं बढ़ी हैं। लगभग एक दशक पूर्व जब भारतीय कंपनी हैवेल्स ने दुनिया भर में सिल्वानिया का कारोबार शुरू किया तो एक युवा परिवार कंपनी के क्षेत्रीय हितों के प्रबंधन के लिए कोस्टारिका चला आया। उसने केवल कंपनी की ही व्यवस्था ही नहीं देखी, बल्कि भारत के ज्ञान का भी विस्तार किया और यहां एक रेस्टोरेंट खोलकर भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक पहलू के प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़ाई।

21 जून, को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान की भावना के अनुरूप 'ताजमहल' रेस्टोरेंट के मालिक कपिल गुलाटी ने भारतीय व्यंजनों की पाक-कला कक्षाओं के साथ-साथ नियमित योग सत्र तथा भारतीय शास्त्रीय नृत्य सत्र का आयोजन किया है। विचार तो ताजमहल में एक लघु भारत प्रस्तुत करने का है ताकि घरों से इतनी दूर रह रहे लोग रहस्य पूर्ण भारत और इसकी संस्कृति का अनुभव कर सकें।

भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को प्रतीक के रूप में उपयोग करते हुए रेस्टोरेंट ने तीन मोर रखे हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा योग करने के दौरान नाचते रहते हैं। इससे वातावरण और भी रमणीक और जीवंत हो जाता है। कोस्टारिका में भारतीय संस्कृति के फलने-फूलने के उदाहरण हैं- रेस्टोरेंट में संगीत वाद्ययंत्र, योग की कक्षाएं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाएं, हिंदी भाषा कक्षाएं, भारतीय पाक कला (व्यंजन) कक्षाएं, भारतीय उत्सव आयोजन, बालीवुड आधारित कोस्टारिका की फिल्में। भारत में कोस्टारिका की राजदूत इस बात का श्रेष्ठ उदाहरण हैं कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार कोस्टारिका के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।

कलियुग में संसार विध्वंस के दौर से गुजर रहा है और जब तक हम अपने से जुड़े रहते हैं और हमें यह ज्ञान है कि हम कहां और क्यों जा रहे हैं, तो हम इस अराजकता में संतुलन बनाए रख सकते हैं। इस कार्य के विभिन्न विकल्पों में योग प्रमुख है। कोस्टारिका रिपब्लिक की राजदूत सुश्री मेरियला क्रुज अल्वारेज का कहना है कि योग कोई धर्म नहीं है, वरन् एक विज्ञान और कला है और इससे पूरी मानवता लाभान्वित हो सकती है।

योग के बारे में एक वृद्ध महिला कहती हैं, ''एक व्यक्तिगत संकट के माध्यम से मेरी योग में दिलचस्पी बढ़ी। मैंने अपने हृदय में उत्तर खोजना शुरू किया और मेरी ये खोज मुझे भारत ले आयी। मैंने पयर्टक के रूप में उत्तर भारत के तीन दौरे किये। इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि दक्षिण भारत जाना चाहिए। मेरी 2003 में कर्नाटक के मैसूर में अपने गुरू श्री के. पट्टाभी जायश और उनके पौत्र शरत जायश से मुलाकात हुई।''

सुश्री अल्वारेज कुल 14 बार भारत की यात्रा कर चुकी हैं, जिसमें एक राजनयिक के रूप में उनकी यह पहली यात्रा भी शामिल है। वह कहती हैं, '' मेरी पिछली 11 यात्राएं भारत स्थित मेरे विद्यालय में गुरूजी के सान्निध्य में और 2009 में गुरूजी के निधन के उपरांत उनके पुत्र शरत जी के सान्निध्य में अष्टांग योग के अभ्यास हेतु थी। मेरा विद्यालय पश्चिम में बहुत लोकप्रिय है और दुनिया भर में कई विद्यार्थी पारंपरिक पद्धति के रूप में योग के लाभों की सराहना करते हैं। योग का स्रोत एवं जनक भारत है और इस तथ्य को जानना इसलिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि अब पश्चिम में बहुत से लोग बगैर किसी योग्यता के योग की शिक्षा दे रहे हैं। व्यावसायिक योग ने योग को आध्यात्मिक साधना की बजाय शारीरिक स्वस्थता तक सीमित कर दिया है।''

कोस्टाकरिका में योग काफी लोकप्रिय हो रहा है और यह योग शिक्षकों, योग आश्रमों, प्रकृति और अभ्यास का केंद्र बन गया है। कोस्टारिका में शानदार समुद्र तट, ज्वालामुखी, और जंगल हैं और योगाभ्यास ने हमें सौंदर्य, शांति और स्वतंत्रता के प्रशंसक के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इन मूल्यों को मेरा देश भली-भांति समझता है। हमारा राष्ट्र हरित विकास का लोकतंत्र है, जो आकार में भले ही छोटा है, लेकिन भावनाओं और सिद्धांतों में बहुत बड़ा है।

30 वर्षों तक एक परिवार का भरण-पोषण करने के बाद दुनिया में अष्टांग योग के अपने पहले मिशन के दूत के रूप में वह कहती हैं, ''भारत में एक दूत के रूप में मेरी आकांक्षा अपने साथियों से खुले दिल के साथ मिलने की है, भले ही वे योगाभ्यास करते हों अथवा नहीं। मेरे इस अभ्यास का उद्देश्य उन लोगों से उपहार स्वीकारना है जो दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और स्वीकृति का भाव रखते हैं। मैं उनको जानकर कृतज्ञ महसूस करती हूं और सहृदय उनकी सराहना करती हूं। गुरूजी शरत जोएस से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त शिक्षा से मुझे लैटिन अमेरिका, यूरोप और भारत में कई शानदार लोगों से मिलने का अवसर मिला है। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है।''

कलियुग में संसार विध्वंस के दौर से गुजर रहा है और जब तक हम अपने से जुड़े रहते हैं और हमें यह ज्ञान है कि हम कहां और क्यों जा रहे हैं, तो हम इस अराजकता में संतुलन बनाए रख सकते हैं। इस कार्य के विभिन्न विकल्पों में योग प्रमुख है।

वह कहती है, ''मैं सभी रूपों में भारत की सराहना करती हूं और जो ज्ञान मुझे यहां प्राप्त हुआ उसने मेरे और मेरे आसपास के लोगों के जीवन को आकांक्षाओं से कहीं बढ़कर परिवर्तित किया है। मेरे गुरूजी कहा करते थे- अभ्यास से सब कुछ संभव है। दुनिया के तमाम लोगों की तरह मैं भी जीवन में मुश्किल समय से गुजरी और ऐसे में योग ने मुझे सहारा देकर मेरा उपचार किया। मेरी आकांक्षा है कि यहां के अपने कार्यकाल के दौरान शांति और स्थायित्व को प्रोत्साहित कर सकूं। पर्यावरण सरोकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य और देखरेख में हमारे प्रयासों के इन्हीं मूल्यों को कोस्टारिका दुनिया को प्रदान करना चाहता है। मुझे कोस्टारिका का निवासी होने पर गर्व है और हमारा देश आपके साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उत्सुक है। हमारे देश की जनसंख्या और भौगोलिक आकार भले ही छोटा हो, लेकिन हमारे इरादे बहुत बड़े हैं। भारत ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। मुझे आशा है कि मैं अपने देश की और आपकी सेवा सर्वोत्तम ढ़ंग से कर सकूंगी।'' ■

(लेखक फाइनेंनशियल एक्सप्रेस में वरिष्ठ संवाददाता हैं और लैटिन अमेरिका पर लिखते हैं)

आपातकाल का एक शर्मनाक अध्याय

जयप्रकाश नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा कि अब नागरिक आजादी की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई।

ए सूर्यप्रकाश

आपातकाल के बाद उपजे बेहद बुरे हालात के लिए संसद का आचरण भी जिम्मेदार था। स्थिति यह थी कि इंदिरा गांधी और उनके बेटे के डर से कांग्रेसी सांसदों ने संविधान में शर्मनाक ढंग से संशोधन करने के लिए होड़ लगा दी थी। इन संशोधनों का मकसद सिर्फ इंदिरा को चुनाव में भ्रष्टाचार के मामले से बच निकलने में मदद पहुंचाना था। कांग्रेस दोनों सदनों में ऐसा करने में इसलिए सफल हो गई थी, क्योंकि एक तो इंदिरा सरकार ने बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को नजरबंद करवा दिया था और दूसरे उसे भाकपा का भरपूर साथ मिला। सच तो यह है कि भाकपा ने इंदिरा की तानाशाही का दिल खोलकर समर्थन किया।

संविधान के 38वें संशोधन के जरिये अदालतों को आपातकाल के फैसले की समीक्षा से वंचित किया गया। इस असाधारण संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव संबंधी याचिका पर सुनावाई से रोक दिया। इसमें कहा गया था कि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संसद एक निकाय गठित करेगी। इसके अतिरिक्त चुनाव संबंधी सभी कानूनों को संविधान की नौंवी अनुसूची में डाल दिया गया। इसको पारित कराने के साथ घोषित किया गया कि अब कोर्ट में चल रही चुनाव संबंधी सभी याचिकाएं खत्म मानी जाएंगी।

फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा उठाए गए बिंदुओं को प्रभावहीन करने के लिए पारित किए गए चुनाव कानून संशोधन एक्ट में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव में धांधली का दोषी पाया जाता है तो उसे अयोग्य ठहराने का फैसला अदालत नहीं, बल्कि राष्ट्रपति करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जिन आरोपों को सही ठहराया था, उसमें से एक यह भी था कि उन्होंने चुनाव अभियान में एक सरकारी कर्मचारी की सहायता ली थी। इसे निष्प्रभावी करने के लिए कानून में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार यदि ड्यूटी के दौरान एक सरकारी अधिकारी चुनाव में उम्मीदवार की मदद करता है तो उसे प्रत्याशी की सहायता करना नहीं समझा जाएगा।

आपातकाल के दौरान संसद का सिर्फ एक ही काम रह गया था और वह था इंदिरा गांधी को बचाने के लिए किसी भी तरह के कानून का निर्माण करना। इसके लिए जहां तक हो संभव हो सका वहां तक संविधान को तोड़ा-मरोड़ा गया। 39वें, 40वें संविधान संशोधन के बाद 41वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव संबंधी याचिका की सुनवाई से दो दिन पहले नौ अगस्त, 1975 को राज्यसभा में पेश किया गया। इसके जरिये अनुच्छेद 361 को संशोधित कर यह कहा गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल के पद पर वर्तमान में या पूर्व में बैठ चुके किसी व्यक्ति द्वारा पद पर रहते हुए या उसके पहले किए गए किसी

कार्य के खिलाफ अदालत में आपराधिक या दीवानी मामले नहीं चलाए जा सकेंगे।

यह असाधारण संशोधन उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में इस तरह का प्रावधान रहना चाहिए जो कुछ नागरिकों को कानून से ऊपर रख दे? इस प्रावधान ने संविधान की जड़ों पर गहरा घात किया, क्योंकि कानून के समक्ष बराबरी और सभी कानूनों का समान क्षमता से प्रयोग हमारे लोकतांत्रिक संविधान की मूल भावना है। हालांकि राज्यसभा ने वह संशोधन बिना किसी बाधा के पारित कर दिया, लेकिन सौभाग्यवश कुछ सोच-विचार के बाद बिल को अपने पास रख लिया। आपातकाल के दौरान जितने भी संविधान संशोधन किए गए उसमें सबसे व्यापक 42वां संशोधन था। उसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के पर कतरना था।

उस संशोधन में कहा गया कि किसी आधार पर किसी भी अदालत में संविधान के किसी भी संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इतना ही नहीं संसद और विधानसभाओं में कानून बनाने के लिए जरूरी न्यूनतम दस प्रतिशत जन प्रतिनिधियों की अनिवार्य मौजूदगी की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई। इसका अर्थ था कि एकमात्र सांसद भी समूचे देश के लिए कानून बना सकता था। न्यायपालिका की ओर से अक्सर यह कहा जाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में यही सबसे जरूरी चीज भी होती है, लेकिन क्या हमारे न्यायाधीश उस इंदिरा सरकार से सामना करने के दौरान इस पर अटल रहे जिसने संविधान को अपाहिज कर दिया था?

नौकरशाही और संसद की तरह ही हमारी न्यायपालिका ने भी हथियार डाल दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की याचिका पर 11 अगस्त, 1975 से सुनवाई आरंभ की और कुछ ही महीने बाद सात नवंबर को फैसला दिया। उसने 39वें संविधान संशोधन और इंदिरा के चुनाव को पिछली तारीखों से वैध घोषित कर दिया। इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला या। मधु दंडवते और लालकृष्ण आडवाणी जैसे कई बंदियों ने हाईकोर्ट में राष्ट्रपति की आपातकाल संबंधी उद्घोषण को चुनौती दी और अपने मौलिक अधिकारों का दावा पेश किया। तब ढेरों नेता मीसा और ऐसे ही अन्य कठोर कानूनों के तहत गिरफ्तार कर लिए गए थे। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों में इन अवैध गिरफ्तारियों के खिलाफ याचिकाओं की बाढ़ गई थी।

सरकार के विधि अधिकारी का तर्क था कि उच्च न्यायालय इन याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिकों के पास अब अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट से गुहार लगाने का अधिकार नहीं रह गया है। एक तर्क यह भी दिया गया कि 27 जून, 1975 को राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद से ही अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) और अनुच्छेद 22 (कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण) के तहत मिले मौलिक अधिकार निरस्त हो गए हैं। हालांकि कई उच्च न्यायालयों को सरकार के इस तर्क दम नजर नहीं या और उन्होंने नजरबंदी के देश निरस्त कर दिए, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में या तो कई जजों ने सरकार के तर्क को स्वीकार लिया।

जयप्रकाश नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा कि अब नागरिक आजादी की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई। इंदिरा की तानाशाही व्यक्तिगत और संस्थागत, दोनों रूपों में सफल हो गई। आपातकाल के दौरान 111000 से ज्यादा लोगों को नजरबंद किया गया था। 25 जून, 1975 की रात भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटने की भरपूर कोशिश हुई थी, लेकिन देश की जनता को नमन कि उसने इंदिरा के प्रयासों को विफल कर दिया। चूंकि मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया था लिहाजा इंदिरा गांधी के पास जनता का मूड भांपने का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं बचा था।

अपने चापलूसों की बातों में कर उन्होंने मार्च 1977 में चुनाव कराने का देश दिया। उन्हें उम्मीद थी कि संसद में उनकी वापसी होगी और वह अपनी तानाशाही जारी रखेंगी, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकीं। जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया और जेल में बने बेतरतीब गठबंधन के हाथों देश की बागडोर सौंप दी। लोगों में आपातकाल की ज्यादतियों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ ऐसा गुस्सा था कि उत्तर और मध्य भारत की 300 लोकसभा सीटों में से पार्टी सिर्फ दो सीटें ही जीत पाई थी। ■

(लेखक (ए सूर्यप्रकाश - सीईओ प्रसार भारती) की शीघ्र प्रकाशित पुस्तक-द इमर्जेंसी : इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट ऑवर का एक अंश, साभार – दैनिक जागरण)

कृषि क्षेत्र का चहुंमुखी विकास

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भारत सरकार द्वारा पूर्व में परिचालित मोडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) की कमियों को दूर करते हुए ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' (PMFBY) 2016 से प्रारम्भ की गई है। नई योजना के तहत रबी में अधिकतम 1.5 प्रतिशत तय की गई है जो आज तक की न्यूनतम दर है। इसमें न सिर्फ खड़ी फसल वरन फसल पूर्व बुवाई तथा फसल कटाई के पश्चात के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्थानीय आपदाओं से क्षति का आकलन पहली बार बीमित खेतवार की जा रही है तथा संभावित दावों का 25 प्रतिशत भुगतान तत्काल ऑनलाइन किया जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह है कि अब बीमित किये जाने वाली राशि पर कैपिंग हटा दी गई है। इसके फलस्वरूप अब किसानों को आज तक की अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि जो फसल लागत मूल्य के बराबर है, मिलेगी। बीमा के दावों के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर काफी जोर दिया गया है, ताकि भुगतान में विलंब न हो।

यहां उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में न सिर्फ किसानों की कुल बीमित राशि बढ़कर करीब 2 गुणा हुई है, वरन गैर-ऋणी किसानों का कवरेज भी वर्ष 2015-16 के 5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 22 प्रतिशत हो गया है जो इस योजना की बढ़ती स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है।

राष्ट्रीय कृषि मंडी (एक देश, एक बाजार)

पहले देश के सभी राज्यों में अलग-अलग मण्डी कानून थे। किसानों के लिए एकल मण्डीय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों से बात कर तीन प्रमुख सुधार यथा इलेक्ट्रॉनिक टेडिंग को मान्यता, एकल बिन्दु पर मार्केट फी एवं एकीकृत लाइसेंस पद्धति किए गए। 14 अप्रैल, 2016 को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय कृषि मण्डी, वेब आधारित ऑनलाइन व्यापार पोर्टल की शुरूआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज देश भर की मण्डियों में बेच रहे हैं। 8 जून, 2017 तक 13 राज्यों की 419 मंडियां, 46 लाख किसान, 90,000 व्यापारी एवं 47,000 कमीशन एजेंट ई-नाम पोर्टल से जुड़ चुके हैं जिनके द्वारा 22,179 करोड़ रुपए की राशि से 96 लाख मीट्रिक टन उत्पादों का कारोबार किया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

वर्ष 2015-16 के पूर्व विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा छोटे स्तर पर अलग-अलग संस्करणों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये जाते थे तथा इसके लिए अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की जाती थी। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए पहली बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

प्रारंभ की गई, जिसमें एक समान मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं परीक्षण पद्धति को अपनाया गया है। इस योजना के माध्यम से 12 मृदा स्वास्थ्य पैरामीटरों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे किसान को अपनी जमीन में उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के जरूरत की सही जानकारी हो सके। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ किसानों के लागत मूल्य में कमी आ रही है, वरन सही पोषक तत्वों की पहचान एवं उपयोगिता भी बढ़ी है। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान रसायनिक उर्वरकों की खपत में 8 से 10 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं उत्पादन में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि वानिकी

वर्तमान सरकार द्वारा मेड़ पर पेड़, खेत में पेड़ तथा intercropping में पेड़ लगाने के उद्देश्य से पहली बार कृषि वानिकी उपमिशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन उन्हीं राज्यों में किया जा रहा है। जहां निजी भूमि पर इमारती लकड़ी की कटाई एवं पारगमन हेतु अधिसूचना में छूट जारी की गई है। इससे न सिर्फ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, मृदा जैविकता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी, वरन यह किसानों के लिए आय का भी स्रोत साबित हो रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 8 राज्य तथा 2017-18 में 5 राज्यों में विनियमन की छूट के उपरांत कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अन्य राज्यों को भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

यह योजना देश में पहली बार वैज्ञानिक एवं समेकित ढंग से स्वादेशी गौवंश नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से 27 राज्यों में 35 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत 31 उच्च नस्ल के मादा गौवंश फार्म (Mother Bull Farm) (नस्लीय सुधार हेतु) गायों के दुग्ध उत्पादकता की रिकॉर्डिंग, 30,000 कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों का प्रशिक्षण

जिससे 6.9 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान इस वर्ष किए गए। साथ ही गौवंश के विशेष संरक्षण हेतु 14 गोकुल ग्राम (गौपशु विकास केन्द्रों) की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी नस्लों के विशेष संरक्षण हेतु 2 कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। इस मिशन से लगभग 7 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसानों व 30 करोड़ गौवंश एवं भैंस वंश की उत्पादकता में सुधार होगा।

राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन

पशुपालकों की आय एवं दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु नवम्बर, 2016 से राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन नामक नई योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत देश में पहली बार 8.8 करोड़ दुधारू पशुओं को नकुल स्वास्थ्य पत्र एवं पशु यूआईडी जारी किए जा रहे हैं। जिससे उनके स्वास्थ्य एवं उत्पादकता की पूर्ण निगरानी एवं सामयिक उपचार हो रहा है। मादा बोवाईन की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से उन्नत प्रजनन तकनीक यथा लिंग सोर्टेड, बोवाईन वीर्य तकनीक, 50 भ्रूण स्थानांतरण केन्द्र और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आई.वी.एफ.) केन्द्र खोले जा रहे हैं।

देशी नस्लों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जेनोमिक केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें जिनोमिक तकनीक के माध्यम से कुछ ही वर्षों में देशी नस्लों को उच्च उत्पादकता हेतु स्वीकार्य बनाया जा सकेगा। यह केन्द्र रोगमुक्त उच्च अनुवांशिक योग्यता वाले सांडों की पहचान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसी क्रम में नवम्बर, 2016 में देश में पहली बार उच्च नस्ल/उत्पादक पशुधन को बेचने वे खरीदने के लिए एवं उच्च नस्ल की वीर्य खुराक की उपलब्धता हेतु देश में पहली बार ई-पशुधन हाट पोर्टल प्रारंभ किया गया है। 12 जून, 2017 तक इस पोर्टल पर 15,831 जीवित पशु, 4.71 करोड़ वीर्य खुराकों तथा 373 भ्रूणों के बारे में सूचना अपलोड की गई है। इसके आधार पर बिना किसी बिचौलिए के पशुधन तथा वीर्य खुराकों की खरीद-फरोख्त में एक पारदर्शी उच्च नस्ल पशु बाजार की स्थाना की गई है। अब तक पोर्टल पर 3 करोड़ वीर्य खुराकों एवं 100 जीवित पशुओं की बिक्री की जा चुकी है।

नीली क्रांति

वर्तमान सरकार ने जल संसाधन की उत्पादकता मछली उत्पादन, मत्स्य पालकों के संरक्षण बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरदेशीय मात्स्यिकी, जल कृषि, समुद्री मात्स्यिकी, मेरीकल्चर, मत्स्य किसानों के लिए बंदरगाहों के विकास जैसे अवयवों के साथ मात्स्यिकी के क्षेत्र की सभी योजनाओं हेतु नीली क्रांति की एक छतरी के नीचे लाया गया है। इसके फलस्वरूप विगत 3 सालों में मछली उत्पादन में 19.75 प्रतिशत वृद्धि एवं बीमित मछुआरों की संख्या में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस सरकार द्वारा बचत-सह-राहत घटक में दी जाने वाली राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसी प्रकार मछुआरों के लिए आवास घटक में राशि 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.30 लाख रुपए कर दिया गया है।

कृषि शिक्षा में स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम

पूर्व में विभिन्न विषयों में हमारे चार वर्षीय कार्यक्रम थे, जिनमें कौशल विकास पर कम जोर तथा मात्र 6 मास का ग्रामीण प्रदर्शन था। वर्तमान में ग्रामीण प्रदर्शन कार्यक्रम को पूरे एक वर्ष का कर दिया गया है, जिससे हमारे डिग्रीधारक जॉब मांगने वाले की बजाय जॉब प्रदाता बन सकेंगे। साथ ही उद्योग वातावरण के प्रदर्शन से छात्रों को उत्पादन प्रक्रियाओं का लाभकारी अनुभ्पव होगा जिससे कालांतर में छात्र कृषि उद्यमों में स्वरोजगार में प्रोत्साहित हो सकेंगे।

कृषि शिक्षा को प्रोफेशनल डिग्री घोषित किया जाना

हाल ही में आई.सी.ए..आर. द्वारा कृषि, बागवानी, मात्स्यिकी एवं वानिकी में 4 वर्ष की कृषि डिग्रियों को व्यावसायिक डिग्री के रूप में घोषित किया है। इससे छात्रों को विभिन्न स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के लिए विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं अध्योवृत्तियां मिलने में मदद मिलती है। साथ ही इससे न सिर्फ कृषि रसायनों, औजारों एवं उपकरणों की डीलरशिप के आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी, वरन प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और निर्यातोन्मुखी व्यवसाय करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

कार्मिक सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं तैनाती तथा स्थानांतरण प्रणाली

उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किये गए हैं जिसके माध्यम से न्यूनतम समय में वैज्ञानिक की संख्या उनका वर्तमान स्तर संसाधन विशेष में नियुक्ति का वर्ष मौजूद रिक्तियां इत्यादि की त्वरित जानकारी मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 468 ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी मिली] जिनकी तैनाती अपने स्वीकृत पदों के अनुसार नहीं थी। इस पर समुचित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटरीकृत तैनाती एवं स्थानांतरण प्रणाली के तहत जानकारी के अभाव में होने वाली अशुद्धियां तथा व्यक्तिक निष्ठा से होने वाली स्थानांतरण पर पूर्णतः रोक लगी है।

ई–शासन के लिए पोर्टल

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा निम्नांकित पोर्टल बनाए गए हैं जिसके फलस्वरूप पूर्ण पारदर्शिता कार्यों का त्वरित निष्पादन अंतिम उपयोगकर्ताओं का फीडबैक तथा संसाधनों एवं किसानों व सिविल सोसाइटी जैसी हितधारकों के बीच दूरी कम करने में मदद मिली है इसके प्रमुख उदाहरण ई-आरपी प्रणाली, केवीके ज्ञान पोर्टल, स्नातकोत्तर एवं शिक्षा हेतु प्रबंधन प्रणाली, शैक्षणिक एवं ई-लर्निंग मॉड्यूल, ई-संवाद, कृषि ई-ऑफिस तथा ई-कृषि मंडी हैं। ■

पीएसएलवी-सी38 ने सफलतापूर्वक एक साथ प्रक्षेपित किए 31 उपग्रह

इसरो ने 23 जून को अपने प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण यान पीएसएलवी से 712 किलोग्राम के कार्टोसैट-2 श्रृंखला के एक उपग्रह और 30 नैनो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह पीएसएलवी का लगातार 39वां सफल मिशन था। पीएसएलवी-सी38 योजना के अनुसार पहले लॉन्च पैड से सुबह नौ बजकर 29 मिनट पर उड़ा और कुछ मिनटों बाद इसने उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया। पीएसएलवी द्वारा लॉन्च कुल भारतीय उपग्रहों की संख्या अब 48 हो गई है।

आने वाले दिनों में उपग्रह अपने पैनक्रोमैटिक (ब्लैक एंड व्हाइट) और मल्टीस्पेक्ट्रल (कलर) कैमरों की मदद से कई तरह की रिमोट सेंसिंग सेवाएं देगा। पीएसएलवी के साथ गए उपग्रहों में एक नैनो उपग्रह तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी जिले की नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। यह एनआईयूसैट फसलों के निरीक्षण और आपदा प्रबंधन के सहयोगी अनुप्रयोगों के लिए तस्वीरें उपलब्ध करवाएगा। दो भारतीय उपग्रहों के अलावा पीएसएलवी के साथ गए 29 नैनो उपग्रह 14 देशों के हैं। ये देश हैं- ऑस्ट्रिया (1), बेल्जियम (3), चिली (1), चेक रिपब्लिक (1), फिनलैंड (1), फ्रांस (1), जर्मनी (1), इटली (3), जापान (1),

लातविया (1), लिथुआनिया (1), स्लोवाकिया (1), ब्रिटेन (3) और अमेरिका (10)। इस सफल प्रक्षेपण के साथ विदेशों से भारत के पीएसएलवी द्वारा कक्षा में स्थापित किए गए ग्राहक उपग्रहों की कुल संख्या 209 पहुंच गई है। ■

केंद्र सरकार ने दलहन के समर्थन मूल्य में 400 रुपए/क्विंटल की वृद्धि की

केंद्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 80 रुपये प्रति क्विंटल और दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी। यह कदम इस सीजन में खरीफ की फसलों का बुआई रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के मकसद से उठाया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून को 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हालांकि अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजकर 2017-18 फसल वर्ष के लिए खरीफ सीजन की फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी के निर्णय की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 80 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1550 रुपये (कॉमन ग्रेड वेरायटी) और 1590 रुपये (ए ग्रेड वेरायटी) करने का निर्णय किया है। दालों के मामले में एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया है।

अरहर का एमएसपी 5050 रुपये से बढ़ाकर 5450 रुपये किया गया है, वहीं मूंग दाल का सपोर्ट प्राइस 5225 रुपये से बढ़ाकर 5575 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उड़द का एमएसपी अब 5000 रुपये के बजाय 5400 रुपये प्रति क्विंटल है।

कपास का एमएसपी 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 4020 रुपये प्रति क्विंटल (मीडियम स्टेपल कॉटन) और 4320 रुपये प्रति क्विंटल (लॉन्ग स्टेपल कॉटन) कर दिया गया है। सोयाबीन का एमएसपी 275 रुपये बढ़ाकर 3050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। छिलके सहित मूंगफली का एमएसपी 230 रुपये और सूरजमुखी का 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब इनके एमएसपी क्रमशः 4450 रुपये और 4100 रुपये प्रति क्विंटल हैं।

मक्का का एमएसपी 60 रुपये बढ़ाकर 1425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरा के मामले में इसे 95 रुपये बढ़ाकर 1425 रुपये और रागी का 175 रुपये बढ़ाकर 1900 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ज्वार (हाइब्रिड) का एमएसपी 75 रुपये बढ़ाकर 1700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन का एमएसपी जितना बढ़ाने की सिफारिश की थी, उससे 200 रुपये ज्यादा बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस साल मॉनसून सीजन में बारिश सामान्य रहने की मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए सरकार रिकॉर्ड अनाज उत्पादन की उम्मीद कर रही है। ■

जीएसटी कार्यान्वयन के पहले दो माह में कर विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया में छूट

जीएसटी के सुगम कार्यन्वयन के उद्देश्य और उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी के दौरान कर विवरण दाखिल करने संबंधी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नियमों में छूट प्रदान की है। जीएसटी लागू होने के प्रथम दो माह में कर आने और जाने वाले सामान का विवरण एक आसान विवरण (प्रपत्र जीएसटीआर-3बी) में देना होगा। इसे अगले माह की 20 तारीख तक जमा किया जा सकेगा। हालांकि नियमित जीएसटीआर-1 को जुलाई और अगस्त माह के लिए निम्नलिखित समय-सीमा अनुसार दाखिल करना होगा।

माह	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर – 1	जीएसटीआर – १ (जीएसटीआर -1से स्वतः लिया गया)
जुलाई, 2017	20 अगस्त	1 – 5 सितंबर	6 – 10 सितंबर
अगस्त, 2017	20 सितंबर	16 – 20 सितंबर	21 – 25 सितंबर

*जुलाई 2017 से बाहर जाने वाली आपूर्ति का विवरण जमा करने के लिए सुविधा 15 जुलाई 2017 से उपलब्ध होगी।

इस अंतरिम अवधि के दौरान कोई विलंब शुल्क या दंड नहीं लगाया जायेगा। इसका उददेश्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करना और प्रणाली में परिवर्तन के अनुरूप ढालने का समय प्रदान करना है। यह केंद्र सरकार की सभी भागीदारों को एक मंच पर साथ लाने के साथ-साथ ऐतिहासिक बदलाव के लिए करदाताओं को तैयार करने की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है। ■

जीएसटी के तहत परिसर, भवन, फ्लैट इत्यादि पर कम टैक्स लगेगा

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और राज्यों को इस आशय की अनेक शिकायतें मिली हैं कि निर्माणाधीन फ्लैटों, परिसर इत्यादि के संदर्भ में जीएसटी के तहत कार्य अनुबंध सर्विस टैक्स 12 फीसदी की दर से लगने के मद्देनजर फ्लैटों की बुकिंग एवं आंशिक भुगतान कर चुके लोगों से यह कहा जा रहा है कि वे या तो 01 जुलाई, 2017 से पहले ही पूरा भुगतान कर दें अथवा 01 जुलाई, 2017 के बाद किए जाने वाले भुगतान पर ज्यादा टैक्स अदा करने के लिए तैयार रहें। यह जीएसटी कानून के विपरीत है। इस मसले को नीचे स्पष्ट किया गया है :

फ्लैटों, परिसर, भवनों के निर्माण पर कम जीएसटी लगेगा, जबकि मौजूदा व्यवस्था के तहत केंद्र एवं राज्यों के अनेक अप्रत्यक्ष कर इन पर लगाए जाते हैं। जीएसटी के तहत समस्त इनपुट क्रेडिट से 12 प्रतिशत की मुख्य दर की भरपाई की जा सकेगी। इसके परिणामस्वरूप फ्लैट में सन्निहित इनपुट टैक्स को फ्लैट की कुल लागत का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।

इस बारे में कानूनन स्थिति स्पष्ट करने बावजूद यदि कोई बिल्डर इस तरह की मनमानी करता है तो वैसे में यह भी माना जा सकता है कि वह जीएसटी कानून की धारा 171 के तहत मुनाफाखोरी कर रहा है।

वर्तमान संयुक्त अप्रत्यक्ष कर दरों के मुकाबले कम हैं जीएसटी दरें

देश में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होने जा रही है, जिसके तहत जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद आपूर्ति पर जीएसटी दरों के निर्धारण की संयुक्त जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों पर होगी।

ज्यादातर वस्तुओं पर जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकृत टैक्स दरें केंद्र एवं राज्यों की वर्तमान संयुक्त अप्रत्यक्ष कर दरों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरों/सन्निहित केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरों/क्लीयरेन्स उपरांत सन्निहित सेवा कर, वैट दरों अथवा भारांक औसत वैट दरों, उत्पाद शुल्क पर वैट की वसूली, सीएसटी, चुंगी, प्रवेश कर इत्यादि की वजह से कर देनदारी) की तुलना में काफी कम हैं। ■

रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी में शुरु राजनीति की पाठशाला

देश में अब नेता बनाने के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की है।

9 माह के पोस्टर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लीडरशिप, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पाठ्यक्रम में छात्रों को लिखित ज्ञान देने के लिए अलावा प्रेक्टिकल ज्ञान देने पर अधिक जोर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगी। रामभाऊ म्हालगी के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक लीडरशिप के तहत यह कोर्स कराया जाएगा। इस कोर्स की फीस ढाई लाख रुपये होगी। पहले बैच में 40 सीटें होंगी।

नौ माह के इस कोर्स के दौरान छात्रों को संस्थान में ही रहना होगा। इसमें हॉस्टल, वाईफाई, जिम समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। राजनेताओं, नौकरशाहों, समाजसेवियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के समय-समय पर भाषण होंगे। एसी कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो की सुविधा भी रहेगी। राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा यह संस्थान पहले से भाजपा नेताओं को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण देता रहा है। भाजपा मंत्रियों के स्टाफ को भी संस्थान ने प्रशिक्षण दिया था।

गत 17 मई को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने इसकी विधिवत शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इससे देश में राजनीतिक क्षेत्र में नए और बेहतर लोग सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि देश में यह चर्चा होती है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। नई पीढ़ी राजनीति से भाग रही है। ऐसे में यह पहल देश की राजनीति के लिए अच्छी साबित होगी। नए व युवा प्रतिभावान राजनेता उभर सकेंगे।

रामभाऊ म्हालगी के अध्यक्ष श्री विनय सहस्त्र बुद्धे ने बताया कि राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना आसान काम नहीं है। इसके लिए कोई फैक्टरी नहीं है। यह एक साधना है। राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक संकल्प, राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था आदि का ज्ञान आवश्यक है। राजनीति दिमाग में आते ही मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति के सकारात्म क पहलू भी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान को लेकर प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, लेकिन उनसे हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं है। हमने इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को लिखित ज्ञान के अलावा व्यावहारिक ज्ञान देने का लक्ष्य रखा है। इस पाठ्यक्रम में कई सारे राजनेताओं और राजनीति से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। देश में सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए रामभाऊ म्हालगी बेहतर प्रयास कर रहा है। ■

विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालयों की तीन साल की उपलब्धियां एवं पहल

केन्द्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने प्रभार वाले मंत्रालयों की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। श्री गोयल ने 12 जून को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सात शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ एवं पटना में मौजूद मीडिया से भी बातचीत की।

श्री गोयल ने बताया कि 'सभी को सातों दिन चौबीस घंटे (24x7) किफायती एवं स्वच्छ बिजली'मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल करना और राष्ट्रीय विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना 'उज्ज्वल भारत' के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के सपने को साकार करने में सहायक साबित होगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालयों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मंत्री महोदय ने यह भी जानकारी दी कि चारों मंत्रालयों ने उज्ज्वल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 6 बुनियादी सिद्धांतों पर काम किया है। इन बुनियादी सिद्धांतों में ये शामिल हैं- सुलभ (सुगम्य बिजली), सस्ती (किफायती बिजली), स्वच्छ (बिजली), सुनियोजित (सोच-समझकर बुनियादी ढांचा तैयार करना, भविष्य के लिए भारत को तैयार करना), सुनिश्चित (सभी के लिए निश्चित बिजली) और सुरक्षित (पारदर्शी गवर्नेंस के साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना)।

बिजली के लिए पर्याप्त कोयला, किल्लत से निजात पाकर अधिशेष की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने वर्ष 2019-20 तक देश में 100 करोड़ टन कोयला उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक के तीन वर्षों की अवधि में कोयला उत्पादन में 9.2 करोड़ टन की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 से पहले इतनी ही वृद्धि हासिल करने में लगभग सात वर्ष लग गये थे।

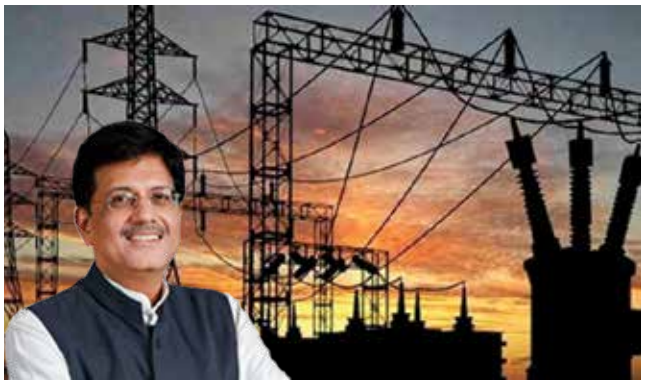

श्री गोयल ने विशेष जोर देते हुए कहा कि इन चारों क्षेत्रों (सेक्टर) से संबंधित समस्त हितधारकों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत क्षेत्र से जुड़े उपक्रमों (सार्वजनिक एवं निजी), खनन क्षेत्र के प्रतिभागियों एवं निवेशकों, उपभोक्ताओं, नागरिकों इत्यादि को भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा करने के एकमात्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपस में समुचित तालमेल बैठाते हुए काम करना होगा।

इन चारों मंत्रालयों की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए श्री गोयल ने निम्नलिखित ब्यौरा दिया :

कोयला

बिजली के लिए पर्याप्त कोयला, किल्लत से निजात पाकर अधिशेष की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने वर्ष 2019-20 तक देश में 100 करोड़ टन कोयला उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक के तीन वर्षों की अवधि में कोयला उत्पादन में 9.2 करोड़ टन की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 से पहले इतनी ही वृद्धि हासिल करने में लगभग सात वर्ष लग गये थे। जहां एक ओर वर्ष 2014 में लगभग दो तिहाई विद्युत संयंत्रों को कोयला स्टॉक की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर फिलहाल कोयले की कोई किल्लत नहीं है। राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला आयात में की गई कमी के जरिए 25,900 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की गई है।

'ज्यादा बिजली के लिए कम कोयले' के सिद्धांत के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। वर्ष 2016-17 में 1 केडब्ल्यूएच बिजली (विशिष्ट कोयला खपत) का उत्पादन करने के लिए 0.63 किलो कोयले का उपयोग किया गया, जबकि वर्ष 2013-14 में इसके लिए 0.69

किलो कोयले का उपयोग किया गया था। यह 8 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। यह न केवल सस्ती, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा (बिजली) भी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, 4 करोड़ टन कोयले के कोल लिंकेज को तर्कसंगत बनाने से लगभग 3,000 करोड़ रुपये की संभावित बचत होगी।

विद्युत

समस्त राज्यों ने 'सभी के लिए बिजली' समझौतों पर दस्तखत कर दिये हैं जो सहकारी संघवाद के सिद्धांत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शक्ति (भारत में कोयले का पारदर्शी ढंग से दोहन एवं आवंटन करने की योजना) कोल लिंकेजों की नीलामी एवं आवंटन की एक परिवर्तनकारी नीति है और इससे सस्ती बिजली, कोयले तक पहुंच और कोयला आवंटन में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मेगा विद्युत नीति से भावी विद्युत खरीद समझौतों के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों का मार्ग प्रशस्त होगा और परियोजनाओं की दीर्घकालिक लाभप्रदता सुनिश्चित होगी।

अप्रैल 2014 से लेकर मार्च, 2017 तक की अवधि के दौरान पारंपरिक बिजली में 60 जीडब्ल्यू की अब तक की सर्वाधिक वृद्धि, परिवर्तनकारी क्षमता में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी

भारत अपनी ऊर्जा दक्षता पहलों के जरिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा है। उजाला (सभी के लिए सस्ती बिजली के जरिए उन्नत ज्योति) के तहत 23 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है।

और पारेषण लाइनों में एक चौथाई से भी ज्यादा की वृद्धि की बदौलत भारत अब एक 'विद्युत अधिशेष (पावर सरप्लस) देश' बन गया है और इसके साथ ही बिजली अथवा कोयले की कोई किल्लत नहीं है। राज्यों के लिए किफायती दरों पर अधिशेष बिजली उपलब्ध होने से 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक दर' की अवधारणा और ज्यादा मजबूत हुई। पहली बार भारत वर्ष 2016-17 में बिजली के एक शुद्ध निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया।

उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना), जिसे वितरण क्षेत्र में एक व्यापक सुधार के रूप में लागू किया गया है, में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है और 2.32 लाख करोड़ रुपये के 'उदय बांडों'को जारी करने की बदौलत डिस्कॉम को लगभग 12,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इस बचत से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराने में मदद मिलेगी। सुधारों की बदौलत विश्व बैंक के 'बिजली पाने में आसानी' सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2015 की 99वीं से सुधर कर वर्ष 2017 में 26वीं हो गई है।

सरकार 'अंत्योदय' से प्रेरित है, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय के दर्शन पर आधारित है और जिसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले तबके के अंतिम व्यक्ति को आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराना है। इस महान दार्शनिक, मानवतावादी और राष्ट्रवादी के जन्म शताब्दी वर्ष को 'गरीब कल्याण वर्ष'के रूप में मनाया जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रमुख योजना (डीडीयूजीजेवाई-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिजली की सुविधा से वंचित शेष 18,452 गांवों (1 अप्रैल, 2015 तक की स्थिति) में से अब 4,000 से भी कम गांव इससे वंचित रह गये हैं और उनका विद्युतीकरण भी मई, 2018 तक हो जायेगा। सरकार ने न केवल प्रत्येक गांव, बल्कि प्रत्येक घर में रोशनी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों द्वारा पेश किये गये आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4.5 करोड़ ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाना अभी बाकी है।

भारत अपनी ऊर्जा दक्षता पहलों के जरिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा है। उजाला (सभी के लिए सस्ती बिजली के जरिए उन्नत ज्योति) के तहत 23 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है और इससे दो उद्देश्य पूरे हुए हैं – जहां एक ओर बिजली के बिलों में 12,400 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली है, वहीं दूसरी ओर कार्बन डाई ऑक्साइड (सीओ2) के उत्सर्जन में 2.5 करोड़ टन से भी ज्यादा की वार्षिक कमी हुई है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि भारत पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, अतः यह हमारे लिए आस्था का विषय है। वर्ष 2016-17 में भारत ने वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने के मिशन के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रतिस्पर्धी बोलियों की शुरुआत करके सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए किफायती एवं आकर्षक साबित हो। वर्ष 2016-17 के दौरान सौर ऊर्जा (2.44 रुपये) और पवन ऊर्जा (3.46 रुपये) दोनों की ही दरें न्यूनतम स्तर पर आ गईं। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि के तहत 2016-17 में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा की शुद्ध क्षमता वृद्धि पारंपरिक ऊर्जा में दर्ज की गई शुद्ध क्षमता वृद्धि के मुकाबले कहीं ज्यादा रही। पिछले वर्ष के दौरान सौर एवं पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में भी अब तक की सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली।

खनन

उपयुक्त नीति एवं प्रौद्योगिकी के संयोजन के जरिए सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की एक योजना शुरू की है। राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति 2016 का उद्देश्य राष्ट्रीय एयरो-भूभौतिकीय मानचित्रण परियोजना के जरिए उत्खनन में तेजी लाना है। इसके तहत वर्ष 2019 तक 27 लाख लाइन किलोमीटर हवाई-भूभौतिकीय आंकड़ों के बारे में डेटा हासिल किया जायेगा, जबकि पिछले 30 वर्षों में केवल 7 लाख लाइन किलोमीटर हवाई-भूभौतिकीय आंकड़ों के बारे में ही डेटा हासिल किया गया था। अपतटीय ब्लॉकों के आवंटन से जुड़ी विधायी रूपरेखा में संशोधन से अपतटीय खनन गतिविधि की शुरुआत हो जायेगी। 24 खनन ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी से खदानों की लीज अवधि के दौरान राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का राजस्व मिलने का अनुमान है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) अवैध खनन की रोकथाम करने के मामले में आकाश में मौजूद एक आंख के रूप में काम करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि खनन से प्रभावित लोग इस गतिविधि से अवश्य ही लाभान्वित हों, सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) शुरू की है, जिसके तहत 12 खनिज समृद्ध राज्यों में से 11 को पहले ही कवर किया जा चुका है। पीएमकेकेकेवाई के तहत जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) ने वर्ष 2016-17 में खनन से लगभग 7150 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं, जिसका उपयोग विशेषकर खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा एवं कल्याणकारी लाभ सुलभ कराने में किया जायेगा।

मोबाइल एप्स के जरिये जवाबदेही एवं पारदर्शिता

सरकार सभी प्रयासों के केन्द्र में 'उपभोक्ता सर्वोपरि है' के सिद्धान्त के साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सर्वोच्च मानकों के तहत भी कार्य कर रही है। विभिन्न विभागों के कामकाज एवं योजनाओं की प्रगति पर

24 खनन ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी से खदानों की लीज अवधि के दौरान राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का राजस्व मिलने का अनुमान है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके खनन निगरानी प्रणाली अवैध खनन की रोकथाम करने के मामले में आकाश में मौजूद एक आंख के रूप में काम करती है।

नजर रखने के लिए विभिन्न एप्स को लांच करना भी इसी का हिस्सा है। पिछले वर्ष लांच किए गये कुछ एप्स में शहरी क्षेत्रों में बिजली की स्थिति और समेकित बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) की प्रगति पर नजर रखने के लिए 'ऊर्जा, पारेषण परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए 'तरंग' एवं बिजली कटौती की सूचना के लिए 'ऊर्जा मित्र' शामिल हैं। चारों मंत्रालयों के सभी एप्स को 18002003004 पर मिस्ड कॉल देकर डाउनलोड किया जा सकता है। ■

मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन

25 जून 2017 को जंगपुरा विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी और मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूर्ण होने पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई। जिसमें 15 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के 205 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। प्रतियोगिता में मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं एवं खेलकूद, महापुरुषों के बारे में, वर्तमान घटनाओं के बारे में प्रश्न दिए गए थे, बच्चों में उत्साह देखते ही बनता था लगभग 4 घंटे के इस कार्यक्रम में बच्चों को प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया गया, अतिथि के रूप में पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री महेश गिरी जी के कार्यालय मंत्री श्री पवन भास्कर जी, लाजपत नगर के निगम पार्षद श्री सुनील सहदेव जी, मयूर विहार जिला के पूर्व अध्यक्ष श्री तेजपाल सिंह जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री विकास चौधरी जी, समाज सेवक एवं गौ सेवक श्री बलराज जी, संघ से लाजपत नगर जिले के नगर कार्यवाह श्री रमेश जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक सर्वश्री रविन्द्र सैनी, राहुल सूद, मंजीत सिंह, करतार सिंह, राकेश हरित, गिरीश शर्मा, विनोद कुमार, कृष्णा गुप्ता और उनका परिवार मुख्य रूप से शामिल रहे।

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

ऊषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की विश्वस्तरीय कृत्रिम ट्रैक के उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करते हुए दक्षिण कोरिया के विशेष दूत जेओंग डांग–छाए

कजाखस्तान की यात्रा के दौरान शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन से इतर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली
36 पृष्ठ कवर सहित

"रजिस्टर्ड"

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

GST: टैक्स दर हुई कम, जन कल्याण की दिशा में बढ़े कदम

आम उपयोग में आने वाली ज्यादातर वस्तुओं पर टैक्स दर हुई कम

उपयोग में आने वाली वस्तुएं	वर्तमान टैक्स रेट	GST
नमक	5%	0
छिलका रहित अनाज	5%	0
खजूर का गुड़	18%	0

उपयोग में आने वाली वस्तुएं	वर्तमान टैक्स रेट	GST
बायो-गैस	12%	5%
बर्फ	12%	5%
छिलके वाला काजू, काजू और किशमिश	12%	5%

उपयोग में आने वाली वस्तुएं	वर्तमान टैक्स रेट	GST
जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, अचार एवं इसे तैयार करने के लिए अन्य सामग्रियां, फल, बादाम	12% - 18%	12%
दाल से बनी बड़ी	18%	12%
केचप और सॉस	18%	12%
करी पेस्ट, सलाद, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर	28%	18%